PRGI Reg. No. : CTHIN/25/A1911

हिन्दी दैनिक

लोकतंत्र प्रहरी

● वर्ष-01 ● अंक- 260 ● भिलाई, शनिवार 25 अप्रैल 2026 ● हिन्दी दैनिक ● पृष्ठ संख्या-8 ● मूल्य - 2 रुपया ● संपादक- संजय तिवारी, मो. 9200000214

पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाकर विकसित भारत की नींव को मजबूत कर रही है हमारी सरकार : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर। डबल इंजन की हमारी सरकार पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाकर विकसित भारत की नींव को मजबूत कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में गांवों के समग्र विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के डीडीयू ऑडिटोरियम में आयोजित पंचायत पदाधिकारी सम्मेलन में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों की सक्रियता से ही गांवों का विकास होगा और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों और पंचायत प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत पंचायत प्रतिनिधि के रूप में की थी तथा पंच और सरपंच के दायित्व का निर्वहन किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि के रूप में गांव के विकास को लेकर जो अनुभव प्राप्त होते हैं, वही आगे बढ़ने में सहायक होते हैं। आज हजारों जनप्रतिनिधि पंचायत से अपना सफर शुरू कर देश के उच्च सदनों तक पहुंचे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों को स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर बनाने में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है और जमीनी स्तर पर बेहतर कार्य करने से ही प्रभावी नीतियां बनती हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब ग्रामीणों को पक्के मकान मिल रहे हैं, साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांवों की कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि अटल डिजिटल सेवा केंद्रों के माध्यम से बैंकिंग, बिजली बिल भुगतान,

पेंशन और बीमा जैसी सेवाएं अब ग्रामीणों के लिए सहज हो गई हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी आई है। महिलाओं के लिए महतारी सदन का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से कई पूर्ण हो चुके हैं और इनसे महिलाओं को सीधा लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री साय ने पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि पंचायतों में संचालित सभी गतिविधियों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करें, ताकि गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ सभी विकास कार्य पूर्ण हो सकें। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सफल क्रियान्वयन में पंचायतों की जिम्मेदारी बढ़ी है और इसे समयबद्ध रूप से पूरा करने में पंचायत प्रतिनिधियों को अपनी सक्रिय भूमिका निभानी होगी। मुख्यमंत्री साय ने सुशासन तिहार के आयोजन का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके माध्यम से आमजनों की समस्याओं के समाधान के लिए शिविर लगाए जाएंगे। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से सुशासन तिहार के आयोजन और इसके माध्यम से अपने क्षेत्र की समस्याओं की पहचान कर उनके समाधान में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना के तहत लंबित बिजली बिलों के भुगतान के लिए विशेष अवसर प्रदान किया जा रहा है, जिसमें सरचार्ज पूरी तरह माफ किया गया है।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक 29 अप्रैल को

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक 29 अप्रैल 2026 को अपरान्ह साढ़े तीन बजे से मंत्रालय (महानदी भवन), नवा रायपुर अटल नगर में आयोजित की जाएगी। इस आशय का पत्र आदिम जाति विकास विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। बैठक में आदिम जाति विकास विभाग के मंत्री एवं जनजातीय सलाहकार के परिषद के उपाध्यक्ष रामविचार नेताम सहित प्रदेश के वरिष्ठ मंत्रीगण, विधायक, प्रशासनिक अधिकारी एवं परिषद के सभी सदस्य उपस्थित रहेंगे। छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में (दिनांक 11 मार्च 2025) के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा के साथ ही कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा भी योजनाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा।

अमित शाह का दावा, भाजपा पश्चिम बंगाल में पहले चरण की 152 में से 110 सीटें जीतेगी

कोलकाता। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 152 सीटों में से 110 सीटें जीतने का दावा करते हुए कहा है कि दूसरे चरण में भी जोरदार जीत हासिल कर वह राज्य में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है।

भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पार्टी ने सभी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ पहले चरण के चुनाव का आकलन किया है और उसमें मिली जानकारी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बंगाल के लोगों ने अपना भविष्य पहले चरण के चुनाव में ही तय कर लिया है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी राज्य में 16 जिलों की 152 सीटों पर हुए चुनाव में से 110 सीटें जीतने जा रही है। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में भी जोरदार जीत के साथ भाजपा पांच मई को राज्य में सरकार बनाने जा रही है। भाजपा नेता ने कहा कि राज्य के लोगों ने भाजपा के पक्ष में मतदान कर विकास की राह को चुना है। उन्होंने कहा कि राज्य में मतदान के सभी पुराने रिकार्ड टूट गये हैं और यह मतदान राज्य में सत्ता में परिवर्तन के लिए भाजपा के पक्ष में हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इन आरोपों पर कि भाजपा की सरकार बनने के बाद राज्य में बाहर का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा इस पर शाह ने कहा , मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बांग्ला माध्यम से पढ़ने वाला और बांग्ला बोलने वाला होगा।

करही गांव में घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग बड़े बेटे की मौत, छोटा बेटा गंभीर रूप से घायल

जांजगीर-चाम्पा। जिले के बिर्रा थाना क्षेत्र के करही गांव में देर रात हुई फायरिंग की वारदात ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। तीन नकाबपोश बदमाशों ने लूट की नीयत से सीमेंट-रेत व्यवसायी सम्मेलाल कश्यप के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी।

इस हमले में व्यवसायी के बड़े बेटे आयुष कश्यप की मौत हो गई, जबकि छोटा बेटा आशुतोष कश्यप गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के मुताबिक देर रात तीन अज्ञात बदमाश घर में दाखिल हुए। आरोपियों ने सबसे पहले घर के अन्य सदस्यों को उनके कमरों में बाहर से बंद कर दिया, ताकि कोई मदद के लिए बाहर न निकल सके। इसके बाद परिवार को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों ने बड़े बेटे आयुष कश्यप पर दो गोलियां चलाईं, जबकि छोटे बेटे आशुतोष कश्यप पर भी एक फायरिंग की गई। गंभीर रूप से घायल आयुष की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आशुतोष के दाहिने हाथ में गोली लगी है। घटना के बाद घायल आशुतोष को तुरंत बिर्रा अस्पताल ले जाया गया।

विधायक ने लिया जायजा

करही गांव में सम्मेलाल कश्यप के घर हुए गोलीकांड के बाद हालात का जायजा लेने विधायक ब्यास कश्यप जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायल परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। बता दें कि सम्मेलाल कश्यप कांग्रेस के ब्लॉक उपाध्यक्ष और व्यवसायी हैं।

अमेरिकी नौसेना प्रमुख फेलन पद से हटाए गए, रक्षा तंत्र में बदलाव तेज

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना प्रमुख जॉन फेलन को पद से बर्खास्त कर दिया है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में यह पहली बार है जब किसी सेवा प्रमुख को पद से हटाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, फेलन को रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के साथ बैठक के बाद इस्तीफा देने को कहा गया। बताया जा रहा है कि ट्रंप को यह लगा कि जहाज निर्माण कार्यक्रम को अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था।

फेलन के स्थान पर सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी हंग काओ को कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है। सूत्रों के अनुसार, यह निर्णय अचानक प्रतीत हुआ, लेकिन इसके पीछे कई महीनों से चल रहे मतभेद थे। नौसेना विस्तार योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर ट्रंप प्रशासन में असंतोष बना हुआ था। ट्रंप ने फेलन को 'अच्छा व्यक्ति' बताते हुए कहा कि वह पेंटागन में अन्य अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित नहीं कर पाए, विशेषकर नए युद्धपोतों के निर्माण और खरीद को लेकर। उन्होंने भविष्य में उनके पुनः शामिल होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया। इस विवाद के केंद्र में अमेरिका की जहाज निर्माण क्षमता को तेजी से बढ़ाने की योजना है।

पीएम मोदी ने की हुगली नदी में नाव की सवारी और फोटोग्राफी

हुगली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कोलकाता में हुगली नदी में नाव की सवारी करते हुए अपनी तस्वीरें साझा कीं।

मोदी द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में उन्हें हाथ में कैमरा लिए एक छोटी नाव पर बैठे देखा जा सकता है, जिसके बैकग्राउंड में विद्यासागर सेतु दिखाई दे रहा है।

मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर हुगली नदी में नाव की सवारी करते हुए तस्वीरें साझा की है। इन तस्वीरों में मोदी फोटोग्राफी करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में प्रधानमंत्री नाव में हाथ में कैमरा लिए नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा, हुगली नदी के किनारों से कुछ और झलकियाँ। इस विशाल नदी की तस्वीरें खींचने की कोशिश की। साथ ही, विद्यासागर सेतु और हावड़ा ब्रिज की भी करीब से झलक मिली। उन्होंने हुगली नदी को पश्चिम बंगाल की संस्कृति से जुड़ा हुआ बताया।

उन्होंने सोशल मीडिया पर हुगली में नाव की सवारी वाली तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, हर बंगाली के लिए, गंगा का एक बहुत ही खास स्थान है। कोई कह सकता है कि गंगा बंगाल की आत्मा में बहती है। इसका पवित्र जल एक पूरी सभ्यता की शाश्वत भावना को अपने साथ समेटे हुए है। उन्होंने लिखा, आज सुबह कोलकाता में, मैंने हुगली नदी के तट पर कुछ समय बिताया—यह माँ गंगा के प्रति आभार व्यक्त करने का एक अवसर था। साथ ही, मुझे वहाँ नाव चलाने वालों से मिलने का भी अवसर मिला, जिनकी कड़ी मेहनत करने की प्रवृत्ति सचमुच सराहनीय है और मैं वहाँ सुबह सैर करने वालों से भी मिला।

उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के मतदाता सूची से हटाए गए निर्वाचन अधिकारियों की याचिकाएं खारिज कीं

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को उन व्यक्तियों की रिट याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिन्हें मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) के बाद पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया था, जबकि वे वर्तमान विधानसभा चुनाव में निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को उन अपीलीय न्यायाधिकरणों (ट्रिब्यूनल) के पास जाने का निर्देश दिया, जिन्हें मतदाता सूची से नाम हटाए जाने की चुनौतियों की सुनवाई के लिए शीर्ष अदालत के आदेश पर गठित किया गया है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एम.आर. शमशाद ने अदालत को बताया कि कई अधिकारियों के नाम बिना किसी कारण के मनमाने ढंग से मतदाता सूची से काट दिए गए हैं।

न्यायमूर्ति बागची ने स्वीकार किया कि जिन लोगों की अपील अभी लंबित है, वे शायद पश्चिम बंगाल के मौजूदा विधानसभा चुनावों में मतदान नहीं कर पाएंगे, लेकिन वे अपनी अपील जारी रख सकते हैं ताकि भविष्य के लिए मतदाता सूची में उनका नाम बहाल किया जा सके। न्यायालय ने बताया कि वर्तमान में लगभग 19 अपीलीय न्यायाधिकरण कार्य कर रहे हैं और वे न्यायिक अधिकारियों के फैसलों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई कर रहे हैं।

इससे पहले 13 अप्रैल को शीर्ष अदालत ने कहा था कि पश्चिम बंगाल के जिन मतदाताओं के नाम चुनाव से कम से कम दो दिन पहले अपीलीय न्यायाधिकरणों द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं, वे विधानसभा चुनाव में मतदान के हकदार होंगे।

रेड्डी ने आरटीसी के चालक शंकर की मौत पर जताया शोक, परिवार को मदद का दिया आश्वासन

हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को सड़क परिवहन निगम (आरटीसी) के चालक शंकर गौड़ की मौत शोक व्यक्त किया। रेड्डी ने अपने शोक संदेश में शोक संतप्त परिवार को आश्वासन दिया कि वे उनके साथ खड़े हैं और सरकार उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने शंकर गौड़ की आत्मा की शांति के लिए और उनके परिवार के सदस्यों को इस क्षति का सामना करने के लिए शक्ति और साहस मिलने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री कहा कि आवेश में लिया गया एक क्षणिक निर्णय परिवार को गहरे दुख में डुबो गया। उन्होंने दोहराया कि सरकार आरटीसी कर्मचारियों के साथ बातचीत कर रही है और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रही है।

गौरतलब है कि आरटीसी कर्मचारियों ने गुरुवार को तेलंगाना में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया।

हमारा विदेश मंत्रालय अभी उन छूटों को लागू करने की कोशिश कर रहा है

ईरान ने रूस और कई अन्य देशों को होर्मुज़ जलडमरूमध्य के शुल्क में दी छूट: जलाली

मास्को। ईरान ने रूस सहित कई देशों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुज़रने के लिए लगने वाले ट्रॉजिट शुल्क में छूट दी है। रूस में ईरान के राजदूत काज़ेम जलाली ने न्यूज एजेंसी स्पूतनिक को यह जानकारी दी। गौरतलब है कि ईरान की संसद के प्रथम उपाध्यक्ष हामिद रज़ा हाजी बाबाई ने गुरुवार को बताया था कि ईरान को पहली बार होर्मुज जलडमरूमध्य को पार करने के शुल्क से राजस्व प्राप्त हुआ है और यह राशि देश के केंद्रीय बैंक में जमा कर दी गयी है।

वहीं जलाली से जब पूछा गया कि क्या ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य के शुल्कों में कोई छूट दी है, तो उन्होंने कहा, हमने फिलहाल कुछ देशों को छूट दी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा। हालांकि, हमारा विदेश मंत्रालय अभी उन छूटों को लागू करने की कोशिश कर रहा है, जो रूस जैसे मित्र देशों के लिए सोची गयी हैं। उल्लेखनीय है कि अमेरिका और इज़रायल के हमले के बाद ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने में आने वाली लागत का हवाला देते हुए, शुल्क लगाने की योजना की घोषणा की थी। अब ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को तब तक के लिए बंद कर दिया है, जब तक कि अमेरिका द्वारा लगाई गयी नौसैनिक नाकेबंदी पूरी तरह से हटा नहीं ली जाती। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इज़रायल की आक्रामकता ने होर्मुज जलडमरूमध्य को प्रभावी रूप से अवरुद्ध कर दिया है। यह जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी के देशों से वैश्विक बाजारों तक तेल और द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलपीजी) की आपूर्ति का एक प्रमुख मार्ग है, और इस अवरोध ने इस क्षेत्र में तेल के निर्यात और उत्पादन पर भी असर डाला है।

रूस ने अफ़ग़ानिस्तान में मानवीय सहायता की पहली खेप भेजी

मास्को। रूस ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) में अपने मुख्य योगदान के तहत अफगानिस्तान में मानवीय सहायता की पहली खेप पहुंचायी है।

रूस के विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। मंत्रालय ने गुरुवार को कहा, 23 अप्रैल को मजार-ए-शरीफ में अफगानिस्तान को रूसी मानवीय सहायता की पहली खेप (फोर्टिफाइड गेहूं का आटा) सौंपने के लिए एक समारोह आयोजित किया गया। मंत्रालय ने बताया कि रूस ने यह सहायता डब्ल्यूएफपी में अपने मुख्य योगदान के हिस्से के तौर पर दी है, और मानवीय सहायता की कुल मात्रा लगभग 3,977 टन होगी।

शांति वार्ता अटकने से लुढ़के शेयर बाजार, आईटी कंपनियों में बिकवाली

मुंबई। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता अटकने से शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजारों में शुरुआती कारोबार में गिरावट देखी गयी, विशेषकर आईटी कंपनियों के शेयरों में सबसे अधिक बिकवाली रही। बीएसई का सेंसेक्स 180.20 अंक टूटकर 77,483.80 अंक पर खुला और इसके बाद लगातार नीचे उतरता गया। खबर लिखे जाते समय यह 762.03 अंक (0.98 प्रतिशत) की गिरावट में 76,901.97 अंक पर था।

अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता में कोई हल न निकलने से बाजार में चौतरफा बिकवाली हो रही है। सभी सूचकांक लाल निशान में हैं। डॉलर के मुकाबले रुपये में जारी गिरावट से भी निवेश धारणा प्रभावित हो रही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 72.50 अंक फिसलकर 100.55 अंक पर खुला। खबर लिखे जाते समय यह 198.90 अंक यानी 0.82 प्रतिशत नीचे 23,974.15 अंक पर था।आईटी सेक्टर पर सबसे अधिक दबाव रहा और इसका सूचकांक दो प्रतिशत से अधिक फिसल गया । मीडिया सेक्टर में भी एक फीसदी से अधिक की गिरावट रही। धातु, ऑटो, बैंकिंग, वित्त, फार्मा और तेल एवं गैस समूहों पर भी ज्यादा दबाव देखा गया। सेंसेक्स की कंपनियों में एचसीएल टेक्नोलॉजीज का शेयर फिलहाल चार प्रतिशत से अधिक नीचे है। इंफोसिस का शेयर भी करीब चार फीसदी नीचे चल रहा है।

शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में धमतरी जिला हो रहा फिसड्डी साबित...

धमतरी। छत्तीसगढ़ के दबंग नेता, पूर्व मंत्री एवं सांसद बृजमोहन अग्रवाल के प्रयास से धमतरी एवं महासमुंद जिले को नेशनल हार्टिकल्चर मिशन की योजनाओं में शामिल किया गया है। यह किसानों के लिये एक वरदान से कम नहीं किंतु बड़े दुर्भाग्य के साथ यहां लिखना पड़ रहा है कि जिनके कंधों पर केंद्र शासन की यह महती योजना के क्रियान्वयन की जवाबदारी है, उस अधिकारी का धमतरी जिले में अता-पता नहीं रहता जिसके चलते किसान इस योजना के लाभ के लिये दर-दर भटक रहे हैं। उक्त अधिकारी कभी-कभार कार्यालय में बैठे रहते हैं तो वहां किसानों के साथ साथ अन्य व्यक्तियों से मिलने में भी गुरेज करते हैं जिससे केंद्र शासन की यह योजना राष्ट्रीय बागवानी मिशन जिसे अब एकीकृत बागवानी विकास मिशन एमआईडीएच के नाम से जाना जा रहा है, प्रभारी अधिकारी की अनुपस्थिति से धमतरी जिला केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के लक्ष्य को पूरा करने में फिसड्डी साबित हो रहा है जिसका मुख्य कारण जिले में पदस्थ प्रभारी अधिकारी की कार्यप्रणाली को माना जा रहा है। धमतरी जैसे उन्नत जिला जहां के किसानों की चर्चा प्रदेश ही नहीं देश में होती है, इसके बावजूद भी जिले में पूर्णकालिक अधिकारी की पदस्थापना नहीं होने से योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। जबकि दूसरी ओर जिले के संवेदनशील कलेक्टर अबिनाश मिश्रा इस चिलचिलाती धूप में जमीनी स्तर पर जाकर शासन की योजनाओं का जायजा लेकर समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने का निर्देश भी दे रहे हैं। वहीं उद्यानिकी विभाग अपने लक्ष्य को भी पूर्ण करने में अक्षम साबित हो रहा है। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिकारियों की भूमिका को अहम माना जाता है और आज प्रत्येक विभाग में स्थायी अधिकारियों की नियुक्ति से जिले भर में उनके अधीन निर्माणाधीन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त होते

रहती है। लेकिन उद्यानिकी विभाग में स्थायी अधिकारी के नहीं रहने से कृषि संबंधी कार्य पर ग्रहण सा लग गया है। जानकारी के अनुसार पिछले दिनों रायपुर में एपीसी की बैठक में भी यही चर्चा थी कि केंद्र की उपरोक्त योजना के क्रियान्वयन में धमतरी जिला बहुत पीछे है। खबर के मुताबिक यहां पदस्थ उद्यानिकी विभाग के उपसंचालक का मुख्य पदस्थापना स्थान रायपुर है जिन्हें धमतरी और कांकेर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। यही वजह है कि धमतरी राष्ट्रीय बागवानी मिशन अब एकीकृत बागवानी विकास मिशन सहित अन्य कई योजनाओं में धमतरी जिला लक्ष्य से काफी दूर है। किसानों का कहना है कि छग शासन के पास उपसंचालक स्तर के अनेक अधिकारी होने के बाद भी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा यहां स्थायी उपसंचालक की नियुक्ति न करना अनेक संदेहों को जन्म देता है। स्थायी उपसंचालक के न होने से जिले के किसानों को एकीकृत बागवानी मिशन की कोई जानकारी नहीं मिल रही है जिसके कारण यह योजना का लाभ किसान नहीं उठा पा रहे हैं। केंद्र सरकार की यह योजना को पूर्व में स्थान नहीं दिया गया था जिसे देखते हुए प्रदेश के दबंग नेता पूर्व मंत्री रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के साथ हो रहे इस अन्याय को केंद्रीय कृषि मंत्री के समक्ष उठाते हुए इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के किसानों को भी मिलने की बात रखी थी जिसे केंद्रीय मंत्री ने स्वीकार करते हुए धमतरी एवं महासमुंद जिला को एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना में शामिल किया है। यह योजना से किसानों को और अधिक लाभ मिलने की संभावना है। लेकिन बिना प्रचार प्रसार के ऐसे किसान इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक हैं और वे इस योजना की जानकारी की लेकर जब उद्यानिकी उपसंचालक कार्यालय में पहुंचते हैं तो वहां अधिकारी अनुपस्थित रहते हैं। पूछने पर उन्हें पता चलता है कि अधिकारी कांकेर अथवा रायपुर से नहीं आये हैं। इस तरह वे मायूस होकर अपने गंतव्य को रवाना हो जाते हैं। उक्त अधिकारी के तीन स्थानों पर प्रभार से शासन की ऐसी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ धमतरी जिले के किसानों को नहीं मिल पा रहा है। जिले के किसानों ने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं कृषि मंत्री रामविचार नेताम से मांग की है कि धमतरी में पदस्थ प्रभारी उपसंचालक के स्थान पर स्थायी उपसंचालक की नियुक्ति कर केंद्र सरकार की इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कर किसानों को उक्त योजना से लाभान्वित किया जाये और यह तभी संभव है जब धमतरी में स्थायी उपसंचालक की नियुक्ति होगी। किसानों ने जिले के संवेदनशील कलेक्टर अबिनाश मिश्रा से मांग की है कि जिले में स्थायी अधिकारी की नियुक्ति के लिये शासन को पत्र लिखना चाहिये ताकि जिले के किसानों को हो रही परेशानियों से निजात मिल सके। वहीं योजनाओं का धमतरी जिले के किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके एवं शासन के लक्ष्य को भी पूर्ण किया जा सके।

लाल बगीचा वार्ड स्थित शिव मंदिर में चोरी की घटना का 24 घंटे में खुलासा

धमतरी। लाल बगीचा वार्ड स्थित प्राचीन शिव मंदिर से भगवान भोलेनाथ जी का पवित्र जल कलश चोरी हो जाना अत्यंत दुःखद एवं निंदनीय घटना थी। इस घटना से समस्त वार्डवासी एवं श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश एवं चिंता का माहौल बन गया था। घटना की जानकारी मिलते ही मंदिर समिति एवं वार्डवासियों द्वारा तत्काल सिटी कोतवाली थाना धमतरी में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सिटी एसपी अभिषेक चतुर्वेदी के निर्देशन में पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्यवाही करते हुए मात्र 24 घंटे के भीतर आरोपी चोर को गिरफ्तार कर लिया तथा भगवान शिव जी का पवित्र जल कलश सुरक्षित बरामद कर पुनः मंदिर समिति को सौंप दिया गया। इस सराहनीय एवं त्वरित कार्यवाही के लिए महिला समिति, समस्त वार्डवासी एवं लाल बगीचा वार्ड पार्षद, सभापति, विधि एवं सामान्य प्रशासन विभाग, नगर निगम धमतरी हिमानी भगवत साहू द्वारा सिटी एसपी अभिषेक चतुर्वेदी एवं उनकी पूरी पुलिस टीम के प्रति हृदय से आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया गया। पुलिस प्रशासन की इस तत्परता से आमजन में सुरक्षा की भावना और कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है।

प्रशासन की सक्रियता से 3 बाल विवाह पर लगी रोक

बलौदाबाजार। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम के द्वारा अक्षय तृतीया के दूसरे दिवस पर बाल विवाह की रोकथाम करने एवं समुदाय के अंतिम व्यक्ति तक बाल विवाह के दूरगामी दुष्प्रभावों की जानकारी का प्रसार करने के लिए बलौदाबाजार भाटापारा एवं पलारी क्षेत्र का भ्रमण किया गया। इस दौरान 3 स्थानों पर बाल विवाह होने से रोका गया। 19 एवं 20 अप्रैल को दो दिवसीय महाअभियान में जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा कुल 75 मामलों में परिवार के घर जाकर हो रहे विवाह में वर - वधु की आयु का परीक्षण किया गया। भाटापारा विकासखण्ड अंतर्गत एक ही परिवार हो रहे दो विवाह में बालिका की आयु 17 वर्ष 6 माह एवं बालक की आयु 19 वर्ष 7 माह की पायी गयी।

जिला बाल संरक्षण इकाई एवं चाईल्ड लाईन की टीम के द्वारा त्वरित कार्यवाही कर बालिका एवं बालिका के परिजनो का बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जानकारी प्रदान कर विवाह हेतु निर्धारित आयु पर ही विवाह करने की समझाईश दी गई। भाटापारा नगर पालिका क्षेत्र में 17 वर्षीय 10 माह की बालिका का विवाह होने की जानकारी प्रदान की गई। उक्त प्रकरण मे वार्ड पार्षद की उपस्थिति में दोना पक्षो को बाल विवाह से बालिकाओं पर पड़ने वाले शारीरिक, मानसिक दुष्परिणामों की जानकारी प्रदान की गई। परिजनो द्वारा अज्ञानतावश अपनी पुत्री का विवाह तय किए जाने की बात स्वीकार करते हुए टीम का आभार व्यक्त किया। बाल विवाह मुक्त जिला बनाए जाने हेतु सामाजिक सहयोग करने एवं बच्चो के सहायतार्थ आपातकालीन हेल्पलाईन नंबर 1098 में सूचना देने का अनुरोध किया गया।

मछली पालन के लिए नगरी, करैहा जलाशय दिए जाएंगे पट्टे पर

धमतरी। जिले के सिंचाई जलाशयों में मछली पालन हेतु शासकीय नियम एवं शर्तों के तहत 10 साल के लिए पट्टा पर दिया जाना है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नगरी ने बताया कि नगरी जलाशय 12.9 हेक्टेयर और करैहा जलाशय 13 हेक्टेयर जलाशय के लिए आवेदन 10 जून तक आमंत्रित किए गए हैं। सिंचाई जलाशय आबंटन संबंधी नियमों की जानकारी जनपद पंचायत कार्यालय नगरी एवं मछलीपालन विभाग से प्राप्त की जा सकती है।

माहुलकोट पंचायत में घटिया निर्माण की खुली पोल पांच लाख की सीसी सड़क हुई जर्जर

गरियाबंद। देवभोग ब्लॉक के ग्राम पंचायत माहुलकोट हाल ही में तैयार की गई सीसी सड़क महज एक महीने के भीतर ही बदहाल हो गई है सड़क की ऊपरी परत कई जगहों से उखड़ चुकी है और दरारों के साथ टूटने भी लगी है जिसे लेकर एजेंसी और अधिकारियों की मिलीभगत से यह सड़क को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने की बात स्थानीय ग्रामीणों द्वारा कही जा रही है जिसका खामियाजा आने वाले दिनों मे लोगो को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जानकारी अनुसार 17 नम्बर 2025 को इस पंचायत में विधायक मद से वार्ड क्रमांक 3 में पाँच लाख की लागत से सीसी सड़क स्वीकृत किया और निर्माण एजेंसी को सड़क बनाने के प्रथम किश्त के रूप 40व का 2 लाख रुपए जारी करने के कई दिनों बाद सड़क गुणवत्ता से समझौता कर बनाया गया क्योंकि एस्टिमेट के तहत सबसे पहले सड़क स्थल पर अच्छी तरह से साफ़ सफाई किया जाता है उसके बाद क़रीब 30 सेंटीमीटर मिट्टी की खुदाई होता तत्पश्चात फेंकी मिट्टी से समतल करते दुर्मुस चलाने का

प्रावधान है साथ ही पर्तो के नीचे रेत भराई करने के बाद सिंचाई करते पुनः दुरुमुस चलाने का नियम है इसके बाद माइक्रान मोटी अपार गम्य पालीथिन बिछाकर 1 घमेला सीमेंट 2 घमेला गिट्टी और 4 घमेला रेती के अनुपात कांक्रीट मसाला इस्तेमाल होता है इस बीच वाइब्रेटर चलाने का फरमान है साथ ही साथ पानी की तराई भी करनी होती हैं मगर अफसोस की बात है की सरपंच सचिव पैसा बचाने की लालसा में ऐसे तमाम नियमों की अनदेखी कर ना सड़क की खुदाई हुई और तय रेती से फीलिंग किया और ना निर्धारित मैटेरियल का इस्तेमाल यहाँ तक पानी की तराई में भी लापरवाही बरता गया शायद यही मुख्य कारण है सड़क की उपरी परत जर्जर होने का जिसकी चिंता न जिम्मेदार अधिकारी को रही और ना निर्माण एजेंसी ग्रामीणों का कहना की सड़क निर्माण के दौरान नियमों की अनदेखी से इंजीनियर एसडीओ सहित सीईओ भी अवगत

सत्यापन के जुगाड़ में जुटे निर्माण एजेंसी

सबसे खास बात तो यह कि इस्टीमेंट और गुणवत्ता से समझौता कर सड़क निर्माण कर दिया और चंद दिन बाद सड़क हालत ख़राब होने की चर्चा गांव की राजनीति गलियारों से लेकर जनपद कार्यालय तक हो रही है फिर भी इस्टीमेंट के विपरीत गुणवत्ताहीन सड़क का सत्यापन कराकर राशि आहरण के लिए जुगाड़ बनाने की कवायत में है जिसे लेकर ग्रामीणों के अलावा वार्ड पंचों में भी नाराजगी है ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण के दौरान मटेरियल समझौता किया वहाँ तक समझ आता है पानी की तराई में कटिमारी हुआ तब जाकर आज सड़क की ऊपरी परत उखड़ रही है और यही हाल रहा तो सड़क में इस्तेमाल नुकीले गिट्टी बाहर आकर आवागमन करने वाले ग्रामीणों को नुक़सान पहुँचाएँगी इसलिए उक्त वार्ड के लोगो में ख़ासी रोष व्याप्त है।

स्थानीय और जिला से सीईओ से भी उम्मीद नहीं

जिला अधिकारियों की निर्माण कार्यों में गुणवत्ता लाने की प्रयास सिर्फ कागजों पर है क्योंकि देवभोग ब्लॉक के कई पंचायतों में सीसी रोड एवं पुलिया गुणवत्ताहीन तरीके से बनाने की खबर अखबारों पटी होती है लेकिन कार्यवाही तो दुर की बात जांच तक नहीं हो पाती जबकि जिला पंचायत सीईओ प्रखर चंद्राकर से लोगो को काफी ज्यादा उम्मीद रही की गुणवत्ता से समझौता कर सड़क पुल निर्माण में रोक लगेगा लेकिन वर्तमान में लोगो की उम्मीद टूटती नजर आ रही है क्योंकि आज भी ग्राम पंचायत में गुणवत्ताहीन तरीक़े से सड़क पुलिया का निर्माण किया जा रहा है जिस पर स्थानीय सीईओ एसडीओ इंजीनियर आँख मूंदे हुए है।

महिला आरक्षण के नाम पर जनता को भ्रमित कर रही भाजपा-अम्बिका मरकाम

धमतरी। नगरी, सिहावा विधायक अंबिका मरकाम ने कहा कि महिला आरक्षण को लेकर केंद्र की मोदी सरकार जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। भाजपा की मंशा महिलाओं को अधिकार देने के बजाय परिसीमन कर राजनैतिक लाभ लेने का था जिसे कांग्रेस व सहयोगी दलों ने विफल कर दिया, यह लोकतंत्र की जीत है। भाजपा ने अपने स्वार्थ के लिये महिला आरक्षण के साथ परिसीमन को जोड़ा था। विधायक अंबिका मरकाम ने कहा कि प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन राष्ट्रहित से अधिक चुनावी लाभ का भाषण था। वर्ष 2023 मे संसद में पारित नारी शक्ति

वंदन अधिनियम को परिसीमन से क्यों जोड़ा गया। भाजपा चाहती थी कि महिला आरक्षण के समर्थन के नाम पर विपक्ष बिल पारित करे और बाद के 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन लागू कर राजनैतिक समीकरण अपने पक्ष में बदल दिया जाय। उन्होंने कहा कि लोकसभा में बिल पास नही होने पर भाजपा इसे मुद्दा बनाकर आडंबर कर रही है। जनता जान रही है कि देश की महिलाओं को मताधिकार से लेकर कई संवैधानिक अधिकार कांग्रेस सरकार में ही मिला है। विधायक अंबिका मरकाम ने जानना चाहा कि जब 2023 मे सर्व सम्मति से महिला आरक्षण विधेयक पारित हो चुका था तो फिर नए विधेयक की आवश्यकता क्यों पड़ी? यदि भाजपा महिलाओं को वास्तविक में आरक्षण देना चाहती है तो वर्तमान 543 लोकसभा सीट से ही महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाये। उसे शीघ्रता से लागू किया जाए। दरअसल भाजपा का असली एजेंडा महिलाओं का अधिकार देना नही, बल्कि परिसीमन की आड़ में राजनीति करना था। उन्होंने यह भी कहा कि अनुसूचित जनजातियों व अनुसूचित जातियों की महिलाओं के अलावा ओबीसी वर्ग की महिलाओं को भी प्रतिनिधि सुनिश्चित किया जाए तथा जनगणना और परिसीमन के नाम पर आरक्षण को टालने की राजनीति बंद हो।

यदि केंद्र सरकार की नियत साफ है तो वह मौजूदा संसदीय सरंचना में ही महिलाओं का आरक्षण लागू करें वर्ष 2023 में जो बिल मूल रूप से महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिये पारित हुआ था उसका कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है।

फुटहामुड़ा नहर परियोजना-निरीक्षण, संवाद से समस्याओं के समाधान की दिशा में तेजी

धमतरी। जिले में संचालित फुटहामुड़ा नहर परियोजना के कार्यों को गति देने तथा कृषकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन हेमलाल कुरेशिया ने मंगलवार को ग्राम जोगीडीह एवं गाड़ाघाट में निर्माणाधीन नहर का स्थलीय निरीक्षण किया तथा वहां के कृषकों के साथ संवाद स्थापित किया। निरीक्षण के दौरान कृषकों द्वारा सिंचाई व्यवस्था, भूमि अर्जन भू.अर्जन एवं निर्माण कार्य से संबंधित विभिन्न समस्याओं को विस्तार से रखा गया। कार्यपालन अभियंता ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके त्वरित एवं व्यवहारिक समाधान के लिए

आश्वस्त किया। उन्होंने बताया कि परियोजना के अंतर्गत प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तकनीकी उपाय किए जा रहे हैं। ग्राम जोगीडीह के कृषकों द्वारा अतिरिक्त सिंचाई सुविधा की मांग पर कार्यपालन अभियंता ने सर्वे कराकर निर्माणाधीन फुटहामुड़ा नहर में लिफ्ट एरिगेशन प्रणाली के माध्यम से ग्राम फुटहामुड़ा तक सिंचाई पहुंचाने का प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित करने की बात कही। इससे क्षेत्र के किसानों को स्थायी सिंचाई सुविधा मिलने की संभावना प्रबल होगी। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर अबिनाश मिश्रा द्वारा सोमवार को परियोजना से प्रभावित ग्रामों के कृषकों की बैठक लेकर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना गया तथा परियोजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, समयसीमा एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए तथा कृषकों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाए। फुटहामुड़ा नहर परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ होगी, जिससे कृषकों की आय में वृद्धि के साथ ही कृषि उत्पादन को भी नई दिशा मिलेगी। जिला प्रशासन इस महत्वाकांक्षी परियोजना को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मगरलोड में कार्यशाला-14 हितग्राहियों के आवेदन स्वीकृत, स्वरोजगार को मिली नई दिशा

धमतरी। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के मार्गदर्शन में मगरलोड जनपद पंचायत में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना पीएमएफएमई के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों को योजना के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी गई, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम में 35 प्रतिशत अनुदान की सुविधा, उद्योग स्थापना की प्रक्रिया तथा फूड प्रोसेसिंग से जुड़े संभावित व्यवसायों के बारे में विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं और किसानों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल रहा है। इस अवसर पर जनपद पंचायत सीईओ दिव्या ठाकुर, उद्योग विभाग की प्रबंधक प्रचेता किरण एवं डीआरपी डॉ संदीप मेश्राम सहित कृषि, उद्यानिकी और अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। क्षेत्र के कृषकों और ग्रामीण हितग्राहियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यशाला के दौरान कुल 14 हितग्राहियों के आवेदन स्वीकृत किए गए, जिससे उन्हें शीघ्र ही योजना का लाभ मिल सकेगा। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करते हुए योजना का अधिकतम लाभ उठाने हेतु प्रोत्साहित किया गया। यह कार्यशाला स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल साबित हुई।

जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा

गरियाबंद। जिला पंचायत के सभाकक्ष में जिला पंचायत अध्यक्ष गौरीशंकर कश्यप की अध्यक्षता में सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायत की उपाध्यक्ष लालिमा ठाकुर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रखर चंद्राकर, जिला पंचायत सदस्यों में संजय नेताम, लोकेश्वरी नेताम, शिवांगी चतुर्वेदी, इंद्रजीत महाड़िक, लेखराज धुर्वा, नंदनी साहू, जनपद पंचायत छुरा की अध्यक्ष मीरा ठाकुर, विधायक प्रतिनिधि सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में जिला पंचायत सीईओ प्रखर चंद्राकर द्वारा शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी गई। ज्ञान भारतम् मिशन के अंतर्गत गांव स्तर पर उपलब्ध दुर्लभ धरोहरों, पुरानी स्मृतियों एवं हस्तलिखित लिपियों का संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु सचिवों को

संबंधित जानकारी फोटो के माध्यम से प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। मोर गांव मोर पानी अभियान अंतर्गत जल संरक्षण का संदेश दिया।

लंबित मुख्यमंत्री आवास योजना अंतर्गत राशि भुगतान के संबंध में विभाग को अवगत कराने के लिए निर्देशित किया। जिला पंचायत अध्यक्ष कश्यप ने अपूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों एवं आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने वनांचल क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, राशन वितरण जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता से सुदृढ़ करने को कहा। विद्युत विभाग को मुख्यमंत्री बिजली भुगतान समाधान योजना के अंतर्गत शिविर लगाकर सक्रिय एवं निष्क्रिय उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में सदस्यों संजय नेताम एवं मीरा ठाकुर द्वारा देवभोग एवं छुरा क्षेत्र में लो-वोल्टेज, ग्रीष्मकालीन विद्युत कटौती एवं जलापूर्ति बाधित होने की समस्याओं से अवगत कराया गया। आदिवासी स्वीकृत आश्रमों के निर्माण, मरम्मत, अहाता निर्माण, स्नानागार एवं शौचालय निर्माण, अतिरिक्त कक्ष, किचन शेड, अधीक्षक आवास तथा सौर ऊर्जा से पेयजल उपलब्धता से संबंधित कार्यों की विस्तृत समीक्षा भी की गई। जल जीवन मिशन के तहत 666 ग्रामों में स्वीकृत योजनाओं की प्रगति, अपूर्ण कार्यों, बोर खनन, हैंडपंप सुधार, पाइप लाइन विस्तार एवं घरेलू नल कनेक्शन की स्थिति पर विभागीय अधिकारियों द्वारा जानकारी प्रस्तुत की गई। पीएम जनमन योजना एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन एवं पूर्ण सड़कों की समीक्षा भी की गई। सदस्य लोकेश्वरी नेताम ने क्रेडा परिसर में प्रस्तावित पुस्तकालय निर्माण हेतु स्थान परिवर्तन का सुझाव दिया। सदस्य संजय नेताम ने 13 स्थानों पर संचालित सौर आधारित विद्युत इकाइयों में सुधार, नई बैटरी स्थापना एवं क्षमता वृद्धि की आवश्यकता बताई। उन्होंने मैनपुर क्षेत्र के मुड़ागेलमाल, धौराझोला एवं साहीडोंगरी के 200 से अधिक किसानों को छैलाडैम एवं केनाल निर्माण से प्रभावित होने पर अतिरिक्त मुआवजा राशि प्रदान करने की मांग रखी। सदस्य इंद्रजीत महाड़िक ने अवैध रेत खनन पर नियमानुसार कार्यवाही करने तथा मुरमुरा से कसेरूडीह तक कच्ची नाली माइनर 220 को पक्का करने की मांग की। क्षेत्र में निर्माणाधीन एनिकेट को गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए। खाद्य विभाग द्वारा राशन वितरण में केवाईसी से संबंधित समस्या उठाते हुए सदस्य -शिवांगी चतुर्वेदी, ज.प. अध्यक्ष मीरा ठाकुर एवं नंदनी साहू ने बताया कि आम जनों को 3 से 5 माह तक राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इ-केवाईसी की जटिलता दुर करने हेतु सरल विकल्प उपलब्ध कराने को कहा। समाज कल्याण विभाग अंतर्गत लंबित वृद्धा एवं दिव्यांग पेंशन को सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन उपरांत शीघ्र जारी किए जाने की जानकारी दी गई।

संक्षिप्त समाचार

मंडी बोर्ड की परीक्षा 26 को,हाफशर्ट व चप्पल पहन देनी होगी परीक्षा

रायपुर। छत्तीसगढ़ व्यापमं द्वारा आयोजित मंडी बोर्ड उप निरीक्षक (सब इंस्पेक्टर) भर्ती परीक्षा 26 अप्रैल को प्रदेशभर में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में कुल 34,168 अभ्यर्थी शामिल होंगे। राजधानी रायपुर सहित विभिन्न जिलों में इसके लिए 104 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक निर्धारित किया गया है। व्यापमं ने अभ्यर्थियों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने के निर्देश दिए हैं। देर से आने वाले उम्मीदवारों को किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।परीक्षा में पारदर्शिता और नकल रोकने के लिए इस बार सख्त ड्रेस कोड लागू किया गया है। अभ्यर्थियों को हल्के रंग के कपड़े पहनकर आना अनिवार्य होगा। काले, गहरे नीले या हरे रंग के कपड़े पहनने पर पाबंदी रहेगी। इसके साथ ही केवल आधी बांह (हाफस्लीव) के कपड़े पहनने की अनुमति होगी, जबकि फुल स्लीव कपड़ों में प्रवेश नहीं मिलेगा।इसके अलावा जूते, मोजे, बेल्ट और स्कार्फ पहनकर आने पर भी रोक लगाई गई है। अभ्यर्थियों को केवल चप्पल पहनकर परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा।परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। गेट पर पुलिस द्वारा सघन जांच (फ्रिस्किंग) की जाएगी।

किशोरी बालिकाओं के लिए नि:शुल्क टीकाकरण अभियान शुरू

रायपुर। जिले में किशोरी बालिकाओं के लिए नि:शुल्क एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरूआत की गई है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में यह जिले के विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों- अभनपुर, गोबरा नवापारा, आरंग, मंदिर हसौद, धरसींवा, तिल्दा, खरोरा सहित मातृ एवं शिशु अस्पताल कालीबाड़ी, डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल तथा एम्स में 17 मार्च 2026 से नियमित रूप से (अवकाश दिवस को छोड़कर) लगाया जा रहा है। यह टीकाकरण विशेष रूप से उन किशोरियों के लिए है, जिन्होंने 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, लेकिन 15 वर्ष की आयु पूरी नहीं हुई है। टीकाकरण के लिए आधार कार्ड या जन्मतिथि अंकित अन्य फोटो पहचान पत्र मान्य होगा। टीकाकरण उपरांत लाभार्थियों का पंजीयन पोर्टल पर किया जाएगा तथा उन्हें डिजिटल प्रमाणपत्र भी प्रदान किया जाएगा।मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश चौधरी ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपनी पात्र पुत्रियों का अवश्य टीकाकरण वश्य कराएं, जिससे उन्हें गर्भाशय ग्रीवा (सर्वाइकल कैंसर) जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखा जा सके। यह अभियान महिलाओं के स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम को सुदृढ़ करना है।

रायपुर में जल्द शुरू होगा नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, निगम ने दिए सख्त निर्देश

रायपुर। राजधानी रायपुर में जल्द ही नेचुरल गैस पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू होने जा रहा है। इस परियोजना के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने हरियाणा सिटी गैस कंपनी को अधिकृत किया है। फिलहाल यह योजना प्रारंभिक चरण में है और कार्य शुरू करने से पहले संबंधित एजेंसी को नगर निगम से अनिवार्य रूप से एनओसी लेना होगा, साथ ही निर्धारित शुल्क भी जमा करना होगा। नगर निगम आयुक्त विश्वदीप ने इस संबंध में गांधी सदन सभागार में बैठक आयोजित कर एजेंसी के प्रतिनिधियों और सभी जोन कमिश्नरों के साथ विस्तृत चर्चा की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि पाइपलाइन बिछाने का कार्य संबंधित जोनों के जल विभाग और नगर निवेश विभाग के अधिकारियों के समन्वय से किया जाए। आयुक्त ने विशेष रूप से कहा कि पाइपलाइन बिछाने के दौरान शहर की पेयजल लाइनों को किसी भी स्थिति में नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इसके अलावा, जहां-जहां खुदाई की जाएगी, वहां सड़कों की तुरंत मरम्मत सुनिश्चित की जाए, ताकि आम नागरिकों को परेशानी न हो। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए कार्य के दौरान नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। बैठक में अपर आयुक्त पंकज शर्मा, विभिन्न जोनों के जोन कमिश्नर, नगर निवेश विभाग के कार्यपालन अभियंता आशुतोष सिंह सहित अन्य अधिकारी और हरियाणा सिटी गैस कंपनी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ में नौकरी के साथ नेतागिरी' पर रोक

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी शासकीय सेवकों के लिए आचरण नियमों के सख्त पालन को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देशों में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के तहत प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्पक्षता, ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना अनिवार्य है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोई भी शासकीय सेवक किसी राजनीतिक दल या संगठन का सक्रिय सदस्य नहीं बन सकता और न ही किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग ले सकता है।

राज्यपाल रमेन डेका ने ली रायपुर जिले में विकासखंड स्तरीय समीक्षा बैठक

अधिकारी जनता के बीच जाएं और करें संवाद-राज्यपाल रमेन

- ग्राम पंचायत स्तर पर जल संरक्षण के लिए डबरी का निर्माण किया जाए
- नशे पर सख्ती से रोक लगाए एवं भारी वाहनों के आवागमन पर करे नियंत्रण

रायपुर/ संवाददाता

राज्यपाल श्री रमेन डेका ने रायपुर जिले की विकासखण्ड स्तरीय समीक्षा बैठक ली। राज्यपाल ने कहा कि सभी अधिकारी जनता बीच जाएं और उनसे मिलें। उनके तथा हितग्राहियों से मुलाकात करें एवं उनकी समस्याओं की जानकारी लेकर योजनाओं का फीडबैक लें। उन्होंने कहा कि जमीनी हकीकत जानने का सबसे बेहतर तरीका लोगों से लगातार संवाद है। राज्यपाल ने जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे प्रोजेक्ट अन्ना, प्रोजेक्ट ग्रीन पालना और प्रोजेक्ट रचना की सराहना की। श्री डेका ने जिले के विभिन्न विकासखण्डों में हो रहे डबरी निर्माण की भी सराहना करते हुए कहा कि हमें बड़े किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, इससे रायपुर के जलस्तर में सुधार आएगा और भविष्य में होने वाले संभावित पेयजल की समस्या का सामना करने में सहयोग मिलेगा। उन्होंने अन्य राज्यों के सफल मॉडलों का उल्लेख करते हुए अधिकारियों को व्यवहारिक और प्रभावी उपाय अपनाने की सलाह दी। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में धान की खेती अधिक होती है, जो पानी की खपत बढ़ाती है, इसलिए बड़े किसानों को अन्य फसलों की ओर भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि रायपुर तेजी से विकसित हो रहा है और आने वाले वर्षों में जल संरक्षण सबसे बड़ी आवश्यकता बन जाएगा। उन्होंने जल जागरूकता, संसाधनों के संरक्षण और उनके सही उपयोग पर विशेष जोर दिया। साथ ही निर्देश दिए कि प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर जल स्रोतों

का पूरा रिकॉर्ड रखा जाए, ताकि उसी आधार पर बेहतर योजना और रणनीति बनाई जा सके। श्री डेका ने कहा कि हमें ग्राम पंचायत स्तर पर छोटी-छोटी डबरी बनानी चाहिए। इस कार्य में समुदाय की भागीदारी अवश्य सुनिश्चित करें और जनप्रतिनिधियों को भी ऐसे कार्यों के लिए शामिल करें। सभी शासकीय कार्यालयों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का निर्माण करें और अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित करें। उन्होंने जल जागरूकता, संसाधनों के संरक्षण और उनके सही उपयोग पर विशेष जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि वृक्षारोपण को अधिक से अधिक बढ़ावा दें। एम्स, डॉ. भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल एवं स्कूलों में वृक्षारोपण करें। सड़कों के किनारे भी वृक्षारोपण किया जा सकता है, इससे प्रदूषण की रोकथाम में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि विकास की निशानी अधिक से अधिक पेड़ लगाना और हरियाली है। प्रोजेक्ट हर घर मुनगा की समीक्षा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि जैविक और प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि जैविक खेती को बढ़ावा दें, नेचुरल फार्मिंग में वैल्यू एडिशन जरूरी है। हमें विशेष रूप से हाइड्रोपोनिक्स को बढ़ावा देना चाहिए। आने वाला समय में इसकी अच्छी संभावना है। उन्होंने नर्सरी हाइड्रोपोनिक्स विकसित करने का सुझाव दिया। ग्रीन पालना परियोजना की चर्चा के दौरान राज्यपाल ने जानकारी ली कि नवप्रसूता महिलाओं को दिए गए पौधों की निगरानी कैसे होती है। वे जीवित हैं या नहीं। राज्यपाल ने कहा कि पेड़ लगाना हम सभी की जिम्मेदारी है और हर व्यक्ति को कम से कम एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। राज्यपाल ने योग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आम जनता से कहा कि योग की कक्षाओं तक ही सीमित न रहें बल्कि योग सीखने के बाद नियमित रूप से घर में भी इसका अभ्यास करें। यातायात व्यवस्था पर राज्यपाल ने कहा कि जिले में भारी वाहनों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तीव्र गति से ड्राइविंग और हेलमेट के मामले में पहले जागरूकता बढ़ाने और फिर आवश्यक होने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने नशे की बढ़ती समस्या पर चिंता जताते हुए कहा कि सख्ती और जागरूकता के जरिए इसे रोकना जरूरी है।

हरा सोना संग्राहकों की आय बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम

- लगभग 920 करोड़ रुपए का होगा संभावित भुगतान
- तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य में जुड़े 13 लाख से अधिक तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार

रायपुर। संवाददाता

छत्तीसगढ़ और अन्य वन क्षेत्रों में तेंदूपत्ता को हरा सोना कहा जाता है, जो आदिवासियों और वनवासियों की आजीविका का मुख्य साधन है। हाल के नीतिगत बदलावों और सरकारी पहलों के कारण इन संग्राहकों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस कार्य से प्रदेश के 13 लाख से अधिक संग्राहक परिवार जुड़े हैं। तेंदूपत्ता संग्राहकों को लगभग 920 करोड़ रुपये का भुगतान होने का अनुमान है। वन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार राज्य शासन द्वारा लघु वनोपज संग्राहकों, विशेषकर आदिवासी समुदाय की आय बढ़ाने के उद्देश्य से तेन्दूपत्ता संग्रहण दर में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। वर्ष 2024 से प्रति मानक बोरा की दर 4 हजार रुपए से बढ़ाकर 5 हजार 500 रुपए कर दी गई है, जिसका सीधा लाभ लाखों ग्रामीण परिवारों को मिलेगा। वर्ष 2026 में राज्य के 31 जिला वनोपज सहकारी यूनियनों के अंतर्गत 902 प्राथमिक समितियों में तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य प्रस्तावित है। इस वर्ष लगभग 15 लाख से अधिक मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहण का अनुमान है। एक मानक बोरे में 1000 गड्डियां होती हैं और प्रत्येक गड्डी में 50 पत्ते शामिल रहते हैं। लगभग 11 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहण होने की संभावनाबस्तर संभाग के 10 जिला यूनियनों की 216 समितियों में करीब 4 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। वहीं अन्य 21 यूनियनों की 868 समितियों में लगभग 11 लाख मानक बोरा संग्रहण होने की संभावना है। इस कार्य से प्रदेश के 13 लाख से अधिक संग्राहक परिवार जुड़े हैं।

अप्रैल में ही आसमान से बरसने लगी आग, छत्तीसगढ़ में तापमान 45 डिग्री के पार

रायपुर। देश के कई हिस्सों में गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। विदर्भ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 44.5 डिग्री तापमान दर्ज हुआ. माना में 44.0, दुर्ग में 43.6 और बिलासपुर में 43.4 डिग्री तापमान रहा। इन इलाकों में भी गर्म हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में कई जगहों पर लू चल सकती है। लोगों को दिन के समय घर से बाहर निकलने में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अप्रैल में ही इतनी गर्मी होना इस बात का संकेत है कि मई और जून में हालात और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं।

मंदिरों की जमीन पर उगा धान खरीदेगी सरकार?

मुख्यमंत्री का बड़ा संकेत,मंदिर महासंघ के गठन से बढ़ी उम्मीदें

रायपुर/ संवाददाता

अक्षय तृतीया पर छत्तीसगढ़ में मंदिरों की ताकत का बड़ा प्रदर्शन, धान खरीदी को लेकर सीएम का संकेत—बदल सकती है पूरी व्यवस्था! रायपुर में धार्मिक ऊर्जा और संगठन शक्ति का ऐसा संगम देखने को मिला जिसने सीधे सत्ता के दरवाजे तक दस्तक दी, 'मंदिर महासंघ, छत्तीसगढ़' के भव्य शुभारंभ के साथ प्रदेश के मठ-मंदिरों को एक मंच पर लाने की ऐतिहासिक पहल हुई और इसी के तुरंत बाद महासंघ का प्रतिनिधिमंडल सीधे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निवास पहुंचा जहां मंदिरों की जमीन पर उगने वाले धान के पंजीकरण और सरकारी खरीदी का बड़ा मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया गया, कार्यक्रम की शुरुआत माँ बम्लेश्वरी के आशीर्वाद और संतों की उपस्थिति में हुई जहां साफ संदेश दिया गया कि अब मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं बल्कि समाज निर्माण और मार्गदर्शन के केंद्र बनेंगे, पूरे प्रदेश से आए मंदिर न्यासों, धर्माचार्यों और हिंदू समाज के प्रतिनिधियों ने एक स्वर में संकल्प लिया कि मंदिरों को संगठित कर उनकी आर्थिक और सामाजिक ताकत को मजबूत किया जाएगा, प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के सामने जो ज्ञापन रखा उसमें सबसे अहम मांग यही रही कि मंदिरों की कृषि भूमि से पैदा होने वाले धान को भी किसानों की तरह पंजीकृत किया जाए और सरकार उसे खरीदे, इस पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए साफसंकेत दिया कि मामला कैबिनेट तक जाएगा और जल्द निर्णय हो सकता है, यही नहीं महासंघ ने बोनस की मांग भी उठाई ताकि मंदिरों की व्यवस्थाएं मजबूत हों और प्राकृतिक आपदाओं में हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकारी सहायता भी सुनिश्चित की जाए।

स्कूल शिक्षा विभाग: एलबी संवर्ग शिक्षकों की सहमति से संविलियन

रायपुर/ संवाददाता

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी संविलियन आदेश के तहत शिक्षक (एल.बी. संवर्ग) की सेवा अवधि की गणना संविलियन 01 जुलाई 2018 से ही की गई है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी संविलियन आदेश 30 जून 2018 के अनुसार, ऐसे शिक्षक जिनकी सेवा अवधि 01 जुलाई 2018 को 08 वर्ष या उससे अधिक पूर्ण हो चुकी थी, उन्हें उनकी सहमति के आधार पर 01 जुलाई 2018 से स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया। उक्त आदेश के प्रावधानों के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि शिक्षक (एल.बी. संवर्ग) को देय समस्त सेवा लाभों के लिए सेवा अवधि की गणना संविलियन दिनांक से ही की जाएगी। राज्य शासन शिक्षकों के हितों के प्रति पूर्णत: प्रतिबद्ध है और पारदर्शिता के साथ सभी प्रावधानों का क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रहा है। शिक्षक (शिक्षक पंचायत/ नगरीय निकाय) के संविलियन उपरांत सेवा गणना एवं पेंशन पात्रता के संबंध में उत्पन्न विभिन्न प्रकार की भ्रांतियों को दूर करते हुए राज्य शासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में सभी प्रावधान नियमानुसार ही लागू किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में शासकीय शालाओं में कार्यरत शिक्षकों (पंचायत/नगरीय निकाय) की प्रारंभिक नियुक्ति पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत शिक्षाकर्मी के रूप में की गई थी, जो शासकीय कर्मचारी की श्रेणी में शामिल नहीं थे। संविलियन प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत/ नगरीय निकाय से स्कूल शिक्षा विभाग में स्थानांतरित शिक्षकों (शिक्षक पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग) को शासकीय सेवकों के समान सेवा लाभ और वेतन सुविधाएं निर्धारित नियमों के तहत देय हैं। छत्तीसगढ़ में प्रमुख संविलियन निर्देश (01 जुलाई 2018) के अनुसार 08 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों का संविलियन किया गया है। 8 वर्ष से कम सेवा वाले शिक्षकों के लिए भी संविलियन की प्रक्रिया अलग-अलग चरणों में पूरी की गई है, जिसके बाद उन्हें समान लाभ मिल रहे हैं। राज्य के प्रचलित सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के अनुसार पेंशन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की नियमित शासकीय सेवा तथा उपदान (ग्रेच्युटी) के लिए न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा आवश्यक है।

इंदौर में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए भाजपा पदाधिकारी

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के पं. दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान के तहत आज इन्दौर में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश भाजपा के पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय सह-संगठन महामंत्री शिवप्रकाश ने अपने प्रबोधन में भाजपा की रीति-नीत, वैचारिक अधिष्ठान व राजनीतिक यात्रा पर मार्गदर्शन किया। इस दौरान भाजपा क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, भाजपा प्रदेश महामंत्री त्रय यशवंत जैन, अखिलेश सोनी व डॉ. नवीन मार्कण्डेय, सांसद द्वय रूपकुमारी चौधरी व लक्ष्मी वर्मा, रामजी भारती, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश लाटिया, श्रीमती रंजना साहू, जी. वेंकटेश्वर, प्रदेश मंत्री हर्षिता पांडेय, प्रदेश कार्यालय मंत्री अशोक बजाज, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता व सांसद संतोष पाण्डेय, नान अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन अनुराग सिंहदेव, प्रशिक्षण महाभियान के प्रदेश संयोजक अवधेश जैन, प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी, शताब्दी पांडेय, टेकेश्वर जैन, डॉ किरण बघेल, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक साहू,बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष वर्णिका शर्मा, आईटी सेल प्रदेश संयोजक सुनील पिल्लई, सोशल मीडिया संयोजक मितुल कोठारी ने भाग लिया

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार जल प्रबंधन को दे रही सर्वोच्च प्राथमिकता

- जलाशय और नहर जीर्णोद्धार से बढ़ेगी कृषि उत्पादकता, किसानों की आय में होगी वृद्धि
- राज्य सरकार की पहल से किसानों के खेतों तक पहुंचेगा भरपूर पानी, बढ़ेगी सिंचाई क्षमता

रायपुर/ संवाददाता

छत्तीसगढ़ में जल प्रबंधन और ग्रामीण अधोसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने आज अम्बिकापुर विधानसभा अंतर्गत उदयपुर विकासखंड में 520 लाख रू. से अधिक लागत के दो महत्वपूर्ण नहर-जलाशय जीर्णोद्धार कार्यों का भूमिपूजन किया। इनमें 265.99 लाख की लागत से डांड़गांव जलाशय बांध एवं नहर जीर्णोद्धार तथा 254.34 लाख रू. की लागत से पंडरीडांड़ जलाशय बांध एवं नहर जीर्णोद्धार कार्य शामिल हैं। यह मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार की जल-प्रबंधन और अधोसंरचना विकास को प्राथमिकता देने वाली नीति का सशक्त उदाहरण है। भूमिपूजन के अवसर पर मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि जलाशयों और नहरों के सुदृढ़ीकरण से क्षेत्र की सिंचाई क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे किसानों को वर्षभर पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा। अन्नदाताओं को स्थायी सिंचाई सुविधा मिलने से वे बहुफसली खेती की ओर अग्रसर होंगे, जिससे उत्पादन में वृद्धि के साथ उनकी आय में भी सीधा इजाफा होगा। उन्होंने बताया कि इस तरह की परियोजनाएं केवल खेतों तक पानी पहुंचाने का कार्य नहीं करतीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने का माध्यम बनती हैं। जलाशयों और नहरों के जीर्णोद्धार से जल संचयन क्षमता बढ़ेगी और भू-जल स्तर में सुधार होगा, जिससे लंबे समय तक सिंचाई की स्थिर व्यवस्था बनी रहेगी। इससे धान के अलावा दलहन, तिलहन और बागवानी फसलों को भी बढ़ावा मिलेगा, जो कृषि विविधीकरण और बाजार आधारित खेती के लिए महत्वपूर्ण है। इससे किसानों की आय में स्थिरता आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। साथ ही पशुपालन और मत्स्य पालन जैसी सहायक गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार देखने को मिलेगा। जल संकट में कमी आने से ग्रामीणों को पेयजल की बेहतर उपलब्धता होगी, वहीं महिलाओं को पानी लाने की कठिनाइयों से राहत मिलेगी।

महापौर ने किया शिविर का समापन

साकेत भवन में कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय ने लगाया विशेष स्वास्थ्य जागरूकता व जांच शिविर

- मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय व श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन के प्रति जताया आभार
- अधिकारी कर्मचारियों का किया गया स्वास्थ्य परीक्षण, विभिन्न बीमारियों की दी आवश्यकता अनुसार दवाईयाँ, दिया गया चिकित्सकीय परामर्श व सुझाव

रायपुर/ संवाददाता

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन के निर्देशानुसार प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों एवं उनके परिवारजनों के स्वास्थ्य की जांच व स्वास्थ्य जागरूकता हेतु आयोजित किये जा रहे शिविरों की कड़ी में कल बुधवार को कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय कोरबा द्वारा निगम कार्यालय साकेत में विशेष स्वास्थ्य जागरूकता व जांच शिविर लगाया गया। महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत ने शिविर का समापन किया तथा मुख्यमंत्री श्री साय व श्रम मंत्री श्री देवांगन के प्रति आभार व्यक्त करते हुये कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय के कार्यों की सराहना की। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन एवं प्रदेश के श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन के दिशा निर्देशों के अनुरूप कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं के द्वारा सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों एवं उनके परिवारजनों के स्वास्थ्य जांच व स्वास्थ्य जागरूकता के संबंध में स्वास्थ्य व जांच शिविर लगाये जा रहे हैं। इसी कड़ी में नगर पालिक निगम कोरबा के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत में बुधवार को प्रात: 11 बजे से शाम 05 बजे तक विशेष स्वास्थ्य जागरूकता व जांच शिविर का आयोजन किया गया, कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय के द्वारा आयोजित उक्त महत्वपूर्ण शिविर में निगम के 500 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। इस दौरान ब्लड प्रेशर, शुगर, जोड़ो का दर्द, सरदर्द, अनिद्रा, हाईपरटेंशन, फीवर, एलर्जी, लीवर, किडनी व हृदय से जुड़ी समस्याओं सहित विविध रोगों की जांच विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा की गई, शिविर में विभिन्न बीमारियों की दवाओं का पर्याप्त स्टाक रखा गया था, अधिकारी कर्मचारियों को चिकित्सकों ने आवश्यकतानुसार दवाईयाँ भी प्रदान की तथा विभिन्न चिकित्सकीय परामर्श व सुझाव दिया।

संपादकीय

पश्चिम एशिया तनाव का असर-महंगाई और गरीबी बढ़ने का बड़ा खतरा

अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच टकराव के मोर्चे स्थायी तौर पर बंद होने की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। दो सप्ताह के युद्धविराम की घोषणा के बीच हाल ही में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में दोनों पक्षों के बीच हुई शांति वार्ता बेनतीजा रहने से जहां अमेरिका का रुख फिर से आक्रामक हो गया है, वहीं ईरान भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार दिख रहा है। पश्चिम एशिया में संघर्ष से उपजे वैश्विक संकट का अगर जल्द समाधान नहीं तलाशा गया, तो इसके व्यापक एवं दूरगामी परिणाम सामने आ सकते हैं। इससे न केवल ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना बेहद मुश्किल हो जाएगा, बल्कि खाद्य सुरक्षा का संकट गहराने की संभावना भी कई गुना बढ़ जाएगी, जिससे सीधे तौर पर आम आदमी का जीवन स्तर प्रभावित होगा। इसका सबसे ज्यादा असर भारत समेत उन देशों पर पड़ेगा, जो अपनी जरूरतों के लिए आयात पर अधिक निर्भर हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की ओर से जारी एक रपट में कहा गया है कि अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच टकराव से उत्पन्न हालात के कारण भारत में पच्चीस लाख लोगों के गरीबी की जद में आने का खतरा है। इस आकलन का आधार यह है कि होर्मुज जलमार्ग के बाधित होने से जहां ईंधन, मालभाड़ा और कच्चे माल की लागत बढ़ रही है, वहीं लोगों की आजीविका कमजोर हो रही है, घरेलू क्रय शक्ति घट रही है और खाद्य असुरक्षा बढ़ रही है। गौरतलब है कि अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच टकराव के मोर्चे स्थायी तौर पर बंद होने की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। दो सप्ताह के युद्धविराम की घोषणा के बीच हाल ही में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में दोनों पक्षों के बीच हुई शांति वार्ता बेनतीजा रहने से जहां अमेरिका का रुख फिर से आक्रामक हो गया है, वहीं ईरान भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार दिख रहा है। ऐसे में अगर होर्मुज जलमार्ग लंबे समय तक बंद रहा, तो इसका असर दुनिया भर में ऊर्जा के गंभीर संकट के रूप में सामने आएगा। भारत की बात की जाए, तो यह अपनी नब्बे फीसद से अधिक तेल जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है और कच्चे तेल का चालीस फीसद से अधिक तथा एलपीजी का नब्बे फीसद आयात पश्चिम एशिया से किया जाता है। इसके अलावा, उर्वरक आयात का पैंतालीस फीसद से अधिक हिस्सा भी इसी क्षेत्र से आता है। इस बात पर गौर करना भी जरूरी है कि भारत के कुल निर्यात का चौदह फीसद और आयात का करीब इक्कीस फीसद व्यापार पश्चिम एशिया से जुड़ा है। ऐसे में यह समझना मुश्किल नहीं होगा कि आने वाले दिनों में देश में किस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है। अमेरिका और ईरान के अड़ियल रवैये से पश्चिम एशिया में युद्ध के मोर्चे दोबारा खुलने की आशंकाओं के बीच संयुक्त राष्ट्र की रपट में कहा गया है कि भारत में गरीबी दर 23.9 फीसद से बढ़कर 24.2 फीसद हो सकती है। जबकि वैश्विक स्तर पर 88 लाख लोग गरीबी के जोखिम में आ सकते हैं, जिनमें भारत समेत दक्षिण एशिया के लोग सबसे अधिक होंगे। इस संकट के बाद देश में गरीबी में रहने वालों की संख्या 35.40 करोड़ तक पहुंच सकती है, जो पहले 35.15 करोड़ थी। जाहिर है कि देश की आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए जीवन-यापन से संबंधित नई मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। इसमें दोराय नहीं कि देश में मौजूदा परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इससे निश्चित तौर पर सरकारी बजट पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है और ऐसे में ज्यादा दिन तक स्थिति को संभालना आसान नहीं होगा। ऐसे में जरूरी है कि सरकार ऊर्जा के नए स्रोत तलाशने के साथ-साथ आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए वैकल्पिक उपायों पर गंभीरता से काम करे, ताकि संभावित संकट के असर को कम किया जा सके।

वैश्विक तनाव के बीच भारत की सधी हुई चाल, ऑस्ट्रिया के साथ सहयोग बढ़ाकर मोदी ने किया कमाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चांसलर स्टॉकर का स्वागत करते हुए इसे विशेष अवसर बताया और इस बात पर जोर दिया कि यूरोप के बाहर अपनी पहली यात्रा के लिए भारत को चुनना ऑस्ट्रिया की भारत के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह यात्रा ऐसे समय में हुई है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के बाद आर्थिक और रणनीतिक सहयोग के नए अवसर सामने आए हैं।

(नीरज कुमार दुबे)

भारत और ऑस्ट्रिया के संबंध पहले से ही अवसंरचना, नवाचार और सतत विकास के क्षेत्रों में मजबूत रहे हैं। दिल्ली मेट्रो और अटल सुरंग जैसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में ऑस्ट्रिया की तकनीकी विशेषज्ञता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

भारत और ऑस्ट्रिया के बीच संबंधों को नई दिशा देने वाली एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल के तहत ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर की भारत यात्रा ऐतिहासिक मानी जा रही है। लगभग चार दशकों के बाद किसी ऑस्ट्रियाई चांसलर का भारत आगमन न केवल द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती का संकेत है, बल्कि यह वैश्विक परिदृश्य में बदलती प्राथमिकताओं के बीच नई साझेदारी के निर्माण का भी प्रतीक है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चांसलर स्टॉकर का स्वागत करते हुए इसे विशेष अवसर बताया और इस बात पर जोर दिया कि यूरोप के बाहर अपनी पहली यात्रा के लिए भारत को चुनना ऑस्ट्रिया की भारत के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह यात्रा ऐसे समय में हुई है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के बाद आर्थिक और रणनीतिक सहयोग के नए अवसर सामने आए हैं।

भारत और ऑस्ट्रिया के संबंध पहले से ही अवसंरचना, नवाचार और सतत विकास के क्षेत्रों में मजबूत रहे हैं। दिल्ली मेट्रो और अटल सुरंग जैसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में ऑस्ट्रिया की तकनीकी विशेषज्ञता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके अलावा रेलवे परियोजनाओं, रोपवे, स्वच्छ ऊर्जा और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में भी ऑस्ट्रियाई कंपनियों की सक्रिय भागीदारी रही है।

दोनों देशों के बीच हुए 15 करार

इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कुल पंद्रह महत्वपूर्ण समझौते और पहलें सामने आईं, जो रक्षा, प्रौद्योगिकी, व्यापार, नवाचार और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों को कवर करती हैं। इनमें सबसे प्रमुख है आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त कार्य समूह की स्थापना का प्रस्ताव, जो वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से निपटने में रणनीतिक सहयोग को मजबूत करेगा।

रक्षा क्षेत्र में भी सहयोग को नई गति देने के लिए सैन्य मामलों में सहयोग पर एक आशय पत्र पर सहमति बनी है। इसके तहत रक्षा उद्योग, नीति संवाद, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। यह पहल भारत और यूरोप के बीच हाल ही में हुए सुरक्षा सहयोग को भी मजबूती प्रदान करेगी।

आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक फास्ट ट्रैक तंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है, जिससे दोनों देशों की कंपनियों और निवेशकों को आने वाली समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जा सकेगा। इससे व्यापार को सुगम बनाने और निवेश को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

सांस्कृतिक और रचनात्मक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए ऑडियो विजुअल सह उत्पादन समझौता किया गया है, जिससे दोनों देशों के फिल्म उद्योग के बीच संयुक्त निर्माण और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, जिसके तहत वैज्ञानिक सहयोग, मानकों के आदान प्रदान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया जाएगा। इससे कृषि और खाद्य उत्पादों के व्यापार को भी मजबूती मिलेगी।

इसके अलावा, दोनों देशों के बीच कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें प्रशिक्षुता प्रणाली, ज्ञान साझा करने और योग्यता की पारस्परिक मान्यता पर जोर दिया गया है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए संरचित संवाद शुरू करने और तकनीकी विश्वविद्यालयों के माध्यम से भारतीय छात्रों के लिए नए अवसर उपलब्ध कराने की पहल भी की गई है।

इस यात्रा के दौरान स्टार्टअप सहयोग को बढ़ाने, साइबर सुरक्षा संवाद शुरू करने, अंतरिक्ष उद्योग में संयुक्त सेमिनार आयोजित करने और वर्किंग हॉलिडे कार्यक्रम को लागू करने जैसी घोषणाएं भी की गईं। उच्च प्रौद्योगिकी जैसे क्वांटम तकनीक, मशीन लर्निंग, जल शोधन और सामग्री विज्ञान में संयुक्त अनुसंधान को साझेदारी का मुख्य आधार बनाया गया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर यह भी कहा कि भारत की प्रतिभा और ऑस्ट्रिया की नवाचार क्षमता मिलकर वैश्विक स्तर पर भरोसेमंद तकनीक और आपूर्ति श्रृंखला विकसित कर सकती है। उन्होंने रक्षा, सेमीकंडक्टर, जैव प्रौद्योगिकी और क्वांटम क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाओं को रेखांकित किया। इसके अलावा, मानव संसाधन के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने प्रगति की दिशा में कदम बढ़ाया है। वर्ष 2023 में हुए प्रवासन और गतिशीलता समझौते के तहत अब नर्सिंग क्षेत्र में भी सहयोग को विस्तार दिया जाएगा। युवा आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए वर्किंग हॉलिडे कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।

साथ ही वैश्विक परिदृश्य पर चर्चा करते हुए दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि सैन्य संघर्ष किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। चाहे यूक्रेन का संकट हो या पश्चिम एशिया की स्थिति, दोनों देशों ने स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया। साथ ही वैश्विक संस्थाओं में सुधार और आतंकवाद के पूर्ण उन्मूलन की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।

हम आपको एक बार फिर बता दें कि ऑस्ट्रिया भारत के लिए एक महत्वपूर्ण यूरोपीय साझेदार है। यह मध्य और पूर्वी यूरोप में प्रवेश का एक प्रमुख द्वार है और हरित प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा तथा उन्नत इंजीनियरिंग में इसकी विशेषज्ञता भारत के विकास कार्यक्रमों के लिए उपयोगी है। दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है और यह लगभग तीन अरब डॉलर के स्तर तक पहुंच चुका है।

वैश्विक परिदृश्य पर क्या असर पड़ेगा?

देखा जाये तो भारत और ऑस्ट्रिया के बीच मजबूत होते संबंधों का प्रभाव वैश्विक भू-राजनीति पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। यूरोप के मध्य में स्थित ऑस्ट्रिया, भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सेतु का काम करता है, जिससे भारत को यूरोप के बाजारों, तकनीक और निवेश तक बेहतर पहुंच मिलती है। इस सहयोग से भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भूमिका और अधिक मजबूत होगी, विशेषकर उच्च प्रौद्योगिकी, रक्षा और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में। इसके साथ ही, ऑस्ट्रिया का भारत के प्रति समर्थन अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति को सुदृढ़ करेगा, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता जैसे मुद्दों पर। दक्षिण एशिया के संदर्भ में यह साझेदारी

भारत की रणनीतिक बढ़त को और मजबूत करेगी, क्योंकि उन्नत तकनीक, रक्षा सहयोग और आर्थिक निवेश के माध्यम से भारत क्षेत्रीय नेतृत्व को और प्रभावी ढंग से स्थापित कर सकेगा। इससे न केवल भारत की सुरक्षा क्षमताएं बढ़ेंगी, बल्कि वह क्षेत्र में स्थिरता, विकास और संतुलन बनाए रखने में भी अधिक सक्षम भूमिका निभा सकेगा।

बहरहाल, ऑस्ट्रिया के चांसलर की भारत यात्रा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दोनों देशों के संबंध अब पारंपरिक सहयोग से आगे बढ़कर नवाचार केंद्रित और भविष्य उन्मुख साझेदारी की ओर अग्रसर हैं। दोनों देशों ने मिलकर एक ऐसे सहयोग मॉडल की नींव रखी है जो न केवल द्विपक्षीय हितों को साधेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी स्थिरता और प्रगति में योगदान देगा। (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

हर सवाल जरूरी नहीं- निजता की सीमा लांघते सवालों से कैसे प्रभावित होता है आत्मसम्मान

(मेघा राठी)

हम ऐसे समाज में रहते हैं, जहां लोग एक-दूसरे के जीवन में बहुत रुचि लेते हैं। यह रुचि कई बार अपनापन लगती है, लेकिन कई बार यही दखलंदाजी बन जाती है। जब कोई सार्वजनिक जगह पर रिश्तों का सहारा लेकर किसी से उसके जीवन के फैसलों पर सवाल करता है, तो वह केवल एक साधारण बात नहीं होती। वह उस व्यक्ति के आत्मसम्मान को छू जाती है। हर इंसान का जीवन उसका अपना होता है।

उसमें उसके सपने होते हैं, उसकी मेहनत होती है, उसकी विफलताएं होती हैं और उम्मीदें भी। हर किसी की गति अलग होती है। कोई जल्दी सफलता पा लेता है, कोई देर से। कोई अपनी राह खुद चुनता है, कोई परिवार की अपेक्षाओं के साथ चलता है। समस्या यह है कि समाज सबके लिए एक ही तरह के मापदंड बना देता है। ऐसे में जो उससे अलग चलता है, वह सवालों के घेरे में आ जाता है।

अक्सर लोग बिना सोचे पूछ लेते हैं- अब तक क्या किया? आगे की क्या योजना है? इतनी उम्र हो गई, अभी तक? ये सवाल सुनने में साधारण लग सकते हैं, पर कई बार ये सामने वाले को असहज कर देते हैं। खासकर तब, जब ये बातें सबके सामने कही जाएं। उस समय व्यक्ति को लगता है कि उसे अपने जीवन का हिसाब देना पड़ रहा है। कई बार सवाल पूछने वाले का इरादा बुरा नहीं होता। वह बस जिज्ञासु होता है या अपने अनुभव के आधार पर सलाह देना चाहता है। मगर हर जिज्ञासा जरूरी नहीं होती। हर बात पूछना आवश्यक नहीं होता। कुछ बातें ऐसी होती हैं, जो व्यक्ति अपने समय पर ही साझा करना चाहता है या नहीं भी करना चाहता है। जब हम बिना सोचे-समझे किसी की निजी बातों में दखल देते हैं, तो हम उसकी सीमा पार कर देते हैं।

सार्वजनिक प्रश्न केवल शब्द नहीं होते, वे संकेत भी होते हैं। वे यह जताते हैं कि समाज को हमारे जीवन की प्रगति पर नजर रखने का अधिकार है। धीरे-धीरे व्यक्ति यह मानने लगता है कि उसे लगातार साबित करना है कि वह पीछे नहीं है। यह मानसिक दबाव अदृश्य होता है, पर बहुत गहरा होता है। कई लोग बाहर से मुस्कुरा देते हैं, हल्का-सा जवाब दे देते हैं, पर भीतर एक चुभन रह जाती है। इस तरह की टिप्पणियां धीरे-धीरे व्यक्ति के मन पर असर डालती हैं। वह अपने फैसलों पर शक करने लगता है। उसे लगता है कि शायद वह पीछे रह गया है। वह दूसरों से अपनी तुलना करने लगता है। कई बार वह अपने ही घर में अपने निर्णयों के लिए सफाई देने लगता है। यह स्थिति उसके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती है।

हम 'मौन' की अहमियत नहीं समझते

जब व्यक्ति बार-बार अपने अस्तित्व को सही ठहराने की कोशिश करता है, तो उसके भीतर की सहजता कम होने लगती है। समस्या यह भी है कि हम 'मौन' की अहमियत नहीं समझते। हमें लगता है कि हर बात पर राय देना जरूरी है, लेकिन कई बार चुप रह जाना ही सबसे अच्छा व्यवहार होता है। अगर कोई अपनी जिंदगी के बारे में खुद बात नहीं करना चाहता, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। सम्मान का मतलब केवल अच्छा व्यवहार करना नहीं है, बल्कि यह समझना भी है कि सामने वाले की एक निजी दुनिया है, जहां हमें बिना बुलाए प्रवेश नहीं करना चाहिए।

हर व्यक्ति अपने जीवन की परिस्थितियों से गुजर रहा होता है। हमें बाहर से सब कुछ साफ दिखाई नहीं देता। जो हमें ठहराव लगता है, वह शायद उसके लिए सीखने का समय हो। जो हमें विफलता दिखती है, वह उसके लिए नई शुरुआत की तैयारी हो सकती है। जो हमें देर लगती है, वह उसके लिए सही समय का इंतजार हो सकता है। इसलिए किसी पर टिप्पणी करने से पहले यह सोचना जरूरी है कि हमारे शब्द उसे कैसा महसूस कराएंगे। भीड़ में पूछे गए प्रश्न अक्सर चिंता से अधिक तुलना का रूप ले लेते हैं।

वह व्यक्ति को यह महसूस कराती है कि उसका मूल्य उसके वर्तमान से नहीं, बल्कि दूसरों से तुलना करके तय किया जा रहा है। दूसरी ओर, व्यक्ति को भी अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीखना चाहिए। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। अगर कोई प्रश्न असहज करता है, तो विनम्रता से विषय बदलना या सीमित उत्तर देना ठीक है।

अपनी सीमाएं तय करना गलत नहीं है। यह आत्मसम्मान का हिस्सा है। जो व्यक्ति अपनी सीमाएं स्पष्ट करता है, वह असम्मान नहीं करता, बल्कि केवल अपनी गरिमा की रक्षा करता है। हमें बच्चों और युवाओं को भी यह सिखाना चाहिए कि उनकी कीमत केवल उपलब्धियों से नहीं तय होती। वे जैसे हैं, अपनी पूरी कोशिश के साथ वैसे ही सम्मान के योग्य हैं। जीवन कोई दौड़ नहीं है, जिसमें सबको एक ही समय पर एक ही स्थान पर पहुंचना हो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और यही उसकी खूबसूरती है। सफलता का एक ही स्वरूप नहीं होता। संतोष, संतुलन और आत्मस्वीकृति भी जीवन की उपलब्धियां हैं। समाज अगर अपने सदस्यों का पूर्ण विकास चाहता है, तो सबसे पहले उसे संवेदनशील बनना होगा। प्रश्न पूछने से पहले ठहरना होगा। यह समझना होगा कि हर जिज्ञासा साझा करने योग्य नहीं होती। कुछ बातें समय पर छोड़ देनी चाहिए। जब हम दूसरों की सीमाओं का सम्मान करना सीखेंगे, तभी हम ऐसे संबंध बना पाएंगे।

तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दहलीज पर भारत, लेकिन रास्ते में ये बड़ी चुनौतियां

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रपट के अनुसार, वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 3.7 ट्रिलियन डालर था। वर्तमान में अमेरिका और चीन क्रमशः पहली और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। आर्थिक विशेषज्ञों और संस्थाओं के आकलन के अनुसार, भारत वर्ष 2030 में जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच सकता है। मगर इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत के सामने अनेक अवसरों के साथ-साथ कई चुनौतियां भी मौजूद हैं।

(अजय जोशी)

भारत की आधुनिक आर्थिक प्रगति की शुरुआत वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों से मानी जाती है। उस समय देश गंभीर भुगतान संतुलन संकट से जूझ रहा था और विदेशी मुद्रा भंडार केवल कुछ सप्ताह के आयात के बराबर ही रह गया था।

वैश्विक परिदृश्य में भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। बढ़ता उपभोक्ता बाजार, आर्थिक वृद्धि में इजाफा और तकनीकी प्रगति से देश विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सम्मिलित हो चुका है। भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल कर लिया है और अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रपट के अनुसार, वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 3.7 ट्रिलियन डालर था। वर्तमान में अमेरिका और चीन क्रमशः पहली और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। आर्थिक विशेषज्ञों और संस्थाओं के आकलन के अनुसार, भारत वर्ष 2030 में जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच सकता है। मगर इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत के सामने अनेक अवसरों के साथ-साथ कई चुनौतियां भी मौजूद हैं।

भारत की आधुनिक आर्थिक प्रगति की शुरुआत वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों से मानी जाती है। उस समय देश गंभीर भुगतान संतुलन संकट से जूझ रहा था और विदेशी मुद्रा भंडार केवल कुछ सप्ताह के आयात के बराबर ही रह गया था। इस स्थिति से उबरने के लिए सरकार ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां अपनाईं। इन सुधारों के परिणामस्वरूप विदेशी निवेश बढ़ा, उद्योगों को नई ऊर्जा मिली और भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव मजबूत हुआ। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 1991 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद लगभग 270 अरब डालर था, जो वर्ष 2000 में करीब 470 अरब डालर तक पहुंच गया। वर्ष 2010 में यह लगभग 1.7 ट्रिलियन डालर हो गया। जबकि 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था करीब 2.9 ट्रिलियन डालर थी। इस तरह वर्ष 2024 में यह लगभग 3.7 ट्रिलियन डालर के आसपास पहुंच चुकी है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि पिछले तीन दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था काफी तेजी से बढ़ी है।

भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना के पीछे मजबूत आधार है। देश में विशाल जनसंख्या के अनुरूप बड़ा उपभोक्ता बाजार है। भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। अर्थव्यवस्था में मध्यम वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 'मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट' की एक रपट के अनुसार, भारत का मध्य वर्ग तेजी से बढ़ रहा है और अनुमान है कि वर्ष 2030 तक इस वर्ग की संख्या पचास करोड़ से अधिक हो सकती है। इसके अलावा भारत के सकल घरेलू उत्पाद में निजी उपभोग का योगदान लगभग साठ फीसद है, जो आर्थिक वृद्धि का महत्वपूर्ण आधार है। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवा है। विश्व बैंक की रपट के अनुसार, भारत की करीब पैंसठ फीसद आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। इसलिए यदि भारत अपने युवा कार्यबल को उचित शिक्षा और कौशल प्रदान करे, तो यह आर्थिक विकास के लिए बड़ा अवसर बन सकता है।

देश में डिजिटल क्रांति ने आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा प्रदान की है। ट्राई और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन आफ इंडिया के अनुसार, भारत में 85 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं और यह संख्या निरंतर बढ़ रही है। इसके अलावा यूपीआइ की डिजिटल भुगतान प्रणाली ने वित्तीय लेन-देन को बहुत आसान बना दिया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2023 में डिजिटल भुगतान प्रणाली के माध्यम से करीब 180 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लेन-देन हुआ।

भारत आज दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल भुगतान बाजारों में से एक है। यहां नवउद्यम भी तेजी से विकसित हुआ है। देश में दिसंबर, 2025 तक डीपीआइआइटी-मान्यता प्राप्त नवउद्यमों की संख्या दो लाख से अधिक हो गई है और इस मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर आता है। इन नवउद्यमों ने लगभग 21 लाख प्रत्यक्ष रोजगार पैदा किए हैं और इनमें 'यूनिकार्न्स' की संख्या 120 से ऊपर पहुंच गई है। फिनटेक, ई-वाणिज्य, स्वास्थ्य, तकनीक और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में नवउद्यम तेजी से नवाचार कर रहे हैं। देश में बुनियादी ढांचे के विकास में बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 के आम बजट में लगभग 11.1 लाख करोड़ रुपए आधारभूत ढांचे के विकास के लिए आवंटित किए गए। आधारभूत ढांचे की उपलब्धता और इससे जुड़ी भावी परियोजनाओं की दृष्टि से भी भारत का तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की संभावनाओं को बल मिलता है।

सड़क परिवहन मंत्रालय और भारतीय रेलवे के आंकड़ों के अनुसार, देश में 1.46 लाख किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। रेलवे नेटवर्क लगभग 68,000 किलोमीटर लंबा है। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। देश को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए भी कई उपाय किए गए हैं। 'मेक इन इंडिया' और उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की योजनाओं के माध्यम से सरकार उद्योगों को प्रोत्साहित कर रही है। इतना सब कुछ होते हुए दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत की राह में बाधाएं भी कम नहीं हैं।

इनमें बेरोजगारी और रोजगार सृजन एक बड़ी चुनौती है। देश में हर वर्ष लगभग एक से डेढ़ करोड़ युवा रोजगार बाजार में प्रवेश करते हैं। सेंटर फार मानिटरिंग इंडियन इकोनामी के अनुसार, भारत की बेरोजगारी दर सात से आठ फीसद के आसपास रहती है। अगर पर्याप्त रोजगार सृजन नहीं होता है, तो यह एक बड़ी आर्थिक और सामाजिक चुनौती बन जाएगी। देश की लगभग 42 फीसद आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान केवल 15-16 फीसद ही है। आज भी सिंचाई और आधुनिक तकनीक की कमी कृषि क्षेत्र में उत्पादन को प्रभावित करती है। देश में आर्थिक विकास के बावजूद आय असमानता बढ़ रही है। आक्सफैम की समानता रपट के अनुसार, भारत के शीर्ष दस फीसद लोग देश की लगभग 70 फीसद संपत्ति को नियंत्रित करते हैं, जबकि निचले तीस फीसद लोगों के पास बहुत कम संपत्ति है। यह असमानता भी सामाजिक और आर्थिक संतुलन के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। भारत में साक्षरता दर लगभग 77 फीसद है, जबकि उच्च शिक्षा में नामांकन दर करीब 28 फीसद है। कई उद्योगों का कहना है कि बड़ी संख्या में स्नातक युवाओं के पास आवश्यक कौशल की कमी है। इसलिए कौशल विकास कार्यक्रमों को मजबूत करना आवश्यक है। इसके अलावा तेजी से बढ़ते औद्योगीकरण और शहरीकरण के कारण पर्यावरणीय समस्याएं भी लगातार बढ़ रही हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में कई भारतीय शहर भी शामिल हैं। नीति आयोग की जल रपट (2018) के आंकड़ों से पता चलता है कि देश के लगभग साठ करोड़ लोग जल संकट का सामना कर सकते हैं। यह समस्या भी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह में बाधा पैदा कर सकती है। यही नहीं, अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध की स्थिति विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर रही है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। इस पहलू पर भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। कुल मिलाकर देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए शिक्षा और कौशल विकास में निवेश को बढ़ावा देना, विनिर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करना, कृषि सुधार और ग्रामीण विकास, तकनीकी नवाचार, डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार तथा पर्यावरणीय संतुलन एवं टिकाऊ विकास की दिशा में प्रभावी कदम उठाने होंगे।

एसडीएम संग बैठक में गोंडवाना समाज ने भूमि हस्तक्षेप का किया कड़ा विरोध

कोंडागांव। गोंडवाना समाज समन्वय समिति, जिला कोंडागांव और एसडीएम के बीच आयोजित बैठक में समाज से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक को दोनों पक्षों ने सार्थक और महत्वपूर्ण बताया, हालांकि भूमि विवाद के मुद्दे पर समाज ने अपना रुख स्पष्ट और कड़ा रखा। बैठक में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में समाज के पदाधिकारी, पारंपरिक व्यवस्था से जुड़े गायता, पुजार्क तथा केशकाल, बड़ेराजपुर, माकड़ी, फरसगांव और कोंडागांव ब्लॉक के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी ने एकमत होकर समाज के निर्णय का समर्थन किया। समाज के प्रतिनिधियों ने गोंडवाना भवन के पीछे स्थित भूमि को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए बताया कि उक्त स्थान पर वर्षों से 'पेन' स्थल स्थापित है, जो गोंडवाना समाज की आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक पहचान का प्रमुख केंद्र है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह केवल भूमि नहीं, बल्कि समाज की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा संवेदनशील विषय है। बैठक के दौरान यह मुद्दा भी सामने आया कि प्रशासन द्वारा न्यायालय के आवासीय परिसर एवं आवागमन मार्ग के निर्माण के लिए उक्त भूमि पर हस्तक्षेप का प्रयास किया जा रहा है। इस पर समाज ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि बुमकाल में पारित प्रस्ताव के अनुसार समाज अपनी भूमि का एक इंच भी देने को तैयार नहीं है। समाज के पदाधिकारियों ने प्रशासन से मांग की कि इस आस्था स्थल को यथावत सुरक्षित रखा जाए और किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि निर्णय लेते समय समाज की धार्मिक भावनाओं और परंपराओं का पूरा सम्मान किया जाए। बैठक के दौरान दोनों पक्षों के बीच सकारात्मक संवाद हुआ, लेकिन गोंडवाना समाज अपने फैसले पर पूरी तरह अडिग नजर आया। अंत में समिति ने प्रशासन से संवेदनशीलता के साथ इस मामले में विचार करने की अपील की।

केशकाल थाने का औचक निरीक्षण पर पहुंचे एडिशनल एसपी, व्यवस्थाओं का लिया जायजा

केशकाल। कोंडागांव जिले के एडिशनल एसपी कपिल चंद्रा बुधवार शाम केशकाल थाना का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने थाना परिसर के सभी कक्षों का बारीकी से निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एडिशनल एसपी ने ड्यूटी पर उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारियों से रूबरू होकर उनकी कार्यप्रणाली, रजिस्टर संधारण एवं लंबित प्रकरणों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए। इस अवसर पर उन्होंने थाना प्रभारी विकास बघेल को कानून-व्यवस्था बनाए रखने, आमजन से बेहतर समन्वय स्थापित करने एवं लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण के संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए। एडिशनल एसपी ने थाना परिसर की साफ-सफाई, अभिलेखों के सुव्यवस्थित रखरखाव एवं अनुशासन बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि आम जनता की शिकायतों का त्वरित और निष्पक्ष निराकरण पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान पुलिस स्टाफ को सतर्क एवं जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी निभाने के लिए भी प्रेरित किया गया।

किरंदुल नगर पालिका ने 21 हितग्राहियों को दी बड़ी राहत, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत भवन अनुज्ञा जारी

किरंदुल। नगरपालिका परिषद किरंदुल द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। इस योजना के तहत आवास निर्माण हेतु गुरुवार नगरपालिका अध्यक्ष रूबी शैलेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष बबलू सिद्दीकी एवम पार्षदों द्वारा कुल 21 हितग्राहियों को भवन अनुज्ञा (परमिशन) प्रदान की गई हैं,जिससे अब वे अपने सपनों का घर बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। नगर पालिका उप अभियंता संजय मार्कण्डेय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार,आवास निर्माण कार्य को चरणबद्ध तरीके से पूर्ण करने पर हितग्राहियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के तहत प्रथम चरणः गड्ढा (फाउंडेशन) खोदने के पश्चात 63,000 की राशि,द्वितीय चरणः लेंटर बीम निर्माण के बाद 87,000 की राशि,तृतीय चरणः छत ढलाई पूर्ण होने पर 65,000 की राशि,चतुर्थ चरणः आवास पूर्ण होने पर ?35,000 की अंतिम किस्त प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त,यदि हितग्राही निर्धारित समयावधि 18 माह के भीतर अपने घर का निर्माण कार्य पूर्ण कर लेते हैं,तो उन्हें गृह प्रवेश योजना के तहत अतिरिक्त 32,850 की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी शशि भूषण महापात्र ने हितग्राहियों से अपील की है कि वे समयसीमा का पालन करते हुए गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य पूर्ण करें,ताकि शासन की योजनाओं का अधिकतम लाभ मिल सके। इस पहल से किरंदुल नगर में आवासीय सुविधाओं का विस्तार होगा और जरूरतमंद परिवारों का जीवन स्तर बेहतर होगा।नगर पालिका अध्यक्ष रूबी शैलेन्द्र सिंह ने कहा कि यह योजना गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी सौगात है और सभी हितग्राहियों को समय पर निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु प्रेरित किया गया है, ताकि वे जल्द से जल्द अपने नए पक्के मकान में प्रवेश कर सकें।

एनएमडीसी के शीर्ष नेतृत्व ने दंतेवाड़ा के पंचायत प्रमुखों से मुलाकात की, जल, बिजली और सड़कों पर कार्रवाई का दिलाया भरोसा

बचेली। समावेशी विकास की दिशा में एक सक्रिय कदम के रूप में, एनएमडीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अमिताभ मुखर्जी ने वरिष्ठ नेतृत्व के साथ दंतेवाड़ा में एनएमडीसी की परियोजनाओं के आसपास के गांवों के पंचायत प्रमुखों के साथ एक बैठक की। बातचीत में जमीनी स्तर की समस्याओं को दूर करने और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सहयोग बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। गुमियापाल, समालवार, कालेपाल, चोलनार, कदमपाल, हिरोली, बेनपाल, कोडेनार, मदकामिरस और कुट्रेम गांवों सहित एक दर्जन से अधिक सरपंचों और उनके प्रतिनिधियों ने पेयजल, सड़क संपर्क, स्वास्थ्य देखभाल, स्ट्रीट लाइटिंग, खेल सुविधाओं और समग्र ग्रामीण बुनियादी ढांचे से संबंधित रोजमर्रा की चुनौतियों के बारे में बात की। बैठक में कृष्ण कुमार ठाकुर, निदेशक (कार्मिक) के साथ-साथ परियोजना के वरिष्ठ अधिकारी के. श्रीधर कोडाली, मुख्य महाप्रबंधक (खनन), बचेली कॉम्प्लेक्स और रवीन्द्र नारायण, अधिशासी निदेशक, किरंदुल कॉम्प्लेक्स शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए सीएमडी ने इस बात पर बल दिया कि एनएमडीसी न केवल एक प्रमुख खनन संगठन बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र के एक जिम्मेदार उद्यम की भी भूमिका निभा रहा है जो क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को समृद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कंपनी की ताकत उन समुदायों के विश्वास में निहित है जिनकी वह सेवा करती है, और उनकी चिंताएं एनएमडीसी के कार्यों का मार्गदर्शन करती हैं। साथ ही, समुदायों की प्रगति एनएमडीसी की सफलता को परिभाषित करती है। उन्होंने कहा, हम इन गांवों के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बस्तियों में बदला जा सके जो विकसित भारत की भावना को दर्शाती हैं। एनएमडीसी की बैलाडीला खदानों के आस-पास के ग्रामीणों ने बेहतर पानी, सड़कों और स्वास्थ्य देखभाल जैसी सुविधाओं पर हुई चर्चा पर प्रसन्नता व्यक्त की। स्थानीय पंचायत के एक प्रतिनिधि ने कहा, वरिष्ठ निदेशकों ने हमसे आमने-सामने बातचीत की और वास्तव में हमारी परेशानियों को सुना। कंपनी के वरिष्ठ निदेशकों की इस प्रत्यक्ष पहुंच ने ठोस बदलाव के लिए नई उम्मीद जगाई है।कृष्ण कुमार ठाकुर, निदेशक (कार्मिक) ने आश्वासन दिया कि एनएमडीसी स्थानीय समुदायों के साथ निरंतर संवाद करता रहेगा और इस बातचीत में साझा की गई समस्याओं से आगामी विकास पहलों को दिशा मिलेगी। बैलाडीला में 1968 में परिचालन शुरू करने के बाद से, एनएमडीसी ने अपने बचेली और किरंदुल परिसरों के माध्यम से औद्योगिक विकास और क्षेत्रीय प्रगति दोनों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन वर्षों में कंपनी दंतेवाड़ा में आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास के उत्प्रेरक के रूप में उभरी है। भारत के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक के रूप में एनएमडीसी का दंतेवाड़ा में 68 वर्षों से गहन विश्वास सहज रूप से पनपा है। एनएमडीसी ने पेयजल परियोजनाएं, सड़कें, खेल के मैदान, क्लीनिक जैसे बड़े बदलाव किए हैं। आज जमीनी स्तर पर हुई बातचीत और आदिवासियों की मूलभूत समस्याओं के आलोक में कमियों को दूर करते हुए इन कार्यों को और आगे बढ़ाया जाएगा।

प्रधान न्यायाधीश ने नेशनल लोक अदालत को अधिक प्रभावी बनाने हेतु बैंक विभाग, दूरसंचार व नगर पालिका के अधिकारियों का लिया बैठक

कोंडागांव। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव खिलावन राम रिगरी की अध्यक्षता में 09 मई 2026 का आयोजित नेशनल लोक अदालत को अधिक प्रभावी बनाने हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में समस्त न्यायिक अधिकारीगण एवं नगर पालिका विभाग, दूरसंचार विभाग समस्त बैंक विभाग के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी 09 मई 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिकतर मामलों का समाधान के लिए रणनीति तैयार करना था। अधिकारियों ने आपसी समन्वय, नोटिस जारी करने की प्रक्रिया ऋण समझौते और बकाया मामलों के समाधान जैसे मुद्दे पर चर्चा किया गया। बैठक के दौरान आगामी 09 मई 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में चर्चा करते हुए नगर पालिका परिषद में लंबित जल कर, दुकान कर, मकान कर, अन्य कर से संबंधित प्रकरण एवं दूरसंचार विभाग के बिल वसूली से संबंधित प्रकरण तथा समस्त बैंकों के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में आपसी राजीनामा के माध्यम से निराकरण करने की समीक्षा की गई। इसके साथ ही प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को यथाशीघ्र प्राधिकरण में प्रस्तुत कर उक्त प्रकरणों को पक्षकारों के मध्य प्री-सिटिंग की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए उक्त आयोजित नेशनल लोक अदालत में अपना सहयोग एवं सहभागिता देते हुए अधिक से अधिक प्रकरणों को निराकृत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

शासकीय आईटीआई बकावंड में तीन दिवसीय कौशल विकास एवं जागरूकता शिविर संपन्न

जगदलपुर। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बकावंड में छात्राओं के सर्वांगीण विकास और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के प्रति तैयार करने के उद्देश्य से आयोजित तीन दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन हुआ। नंदी फाउंडेशन के तत्वावधान में 20 अप्रैल से 22 अप्रैल तक चले इस शिविर के माध्यम से छात्राओं को कौशल विकास के साथ-साथ वर्तमान समय की अनिवार्य व्यावहारिक जानकारियों से लैस किया गया। प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञ प्रशिक्षकों ने छात्राओं को आज के डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति सचेत करते हुए सुरक्षित इंटरनेट बैंकिंग और डिजिटल सुरक्षा के महत्वपूर्ण गुर सिखाए। कार्यक्रम में विशेष रूप से बैंकिंग धोखाधड़ी और फर्जी कॉल से बचने के तरीकों पर विस्तृत चर्चा की गई, ताकि छात्राएं स्वयं के साथ-साथ अपने परिवार को भी वित्तीय जोखिमों से सुरक्षित रख सकें। इसके अतिरिक्त, महिला सुरक्षा और जागरूकता से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए उन्हें समाज में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर सभी प्रतिभागी छात्राओं को उनकी सक्रिय सहभागिता के लिए प्रमाण-पत्र वितरित किए गए। इस मौके पर संस्था के प्राचार्य डॉएके मांडले ने छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए प्रशिक्षण की महत्ता पर जोर दिया।

केशकाल में जैन गुरु भगवन्तों का मंगलमय प्रवेश, श्रद्धालुओं में उमड़ा उत्साह

केशकाल। नगर में जैन धर्म के पूज्य गुरु भगवन्तों का भव्य एवं मंगलमय प्रवेश हुआ। कोण्डागांव से विहार करते हुए जब संतों का केशकाल आगमन हुआ, तो जैन धर्म के अनुयायियों का हुजूम उमड़ पड़ा। डिपो चौक से बैंड-बाजे के साथ जैन समाज के महिला मंडल, पुरुषों एवं बच्चों ने उत्साहपूर्वक अगुवानी की और पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। जैन संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि केशकाल के लिए यह अत्यंत गौरव का विषय है कि ऐसे तपस्वी संतों का सानिध्य नगरवासियों को प्राप्त हो रहा है, जो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि सात मुनियों का एक साथ आगमन पूरे क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है। इस अवसर पर विशेष रूप से तपस्वी सम्राट मुनि वीरभद्र मुनि (विराग मुनि) चर्चा का केंद्र रहे, जो अपनी कठोर तपस्या के लिए देशभर में प्रसिद्ध हैं। बताया गया कि वे वर्तमान में अपने 113वें उपवास पर हैं, जिसमें वे केवल जल ग्रहण करते हैं और अन्न का पूर्ण त्याग करते हैं। भीषण गर्मी के बावजूद उनकी यह तपस्या श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा और अनुकरणीय उदाहरण बन रही है। मुनि पन्यास प्रवर विनय कुशल मुनि जी सहित कुल सात मुनियों के इस भव्य प्रवेश से जैन समाज में हर्ष का वातावरण है। सभी मुनि मंदिर जी के उपासरे में विराजमान हैं, जहां प्रतिदिन प्रातः 8:45 बजे से उनके प्रवचन होंगे।

जैन समाज ने नगरवासियों से अपील की है कि वे गुरु वंदन, सुपात्र दान एवं प्रवचनों में भाग लेकर इस दिव्य अवसर का लाभ उठाएं। उल्लेखनीय है कि मुनियों का केशकाल में लगभग पांच दिनों तक प्रवास प्रस्तावित है, जिसे लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है।

एनएमडीसी सीएमडी के किरंदुल प्रवास पर इंटक यूनियन ने 20 सूत्रीय मांग पत्र पर सकारात्मक कार्यवाही की मांग की

किरन्दुल। एनएमडीसी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक सीएमडी अमिताव मुखर्जी, निदेशक टेक्निकल, निदेशक उत्पादन, निदेशक कार्मिक, निदेशक वित्त,के बीआईओएम किरंदुल काम्प्लेक्स प्रवास पर मेटल माइंस वर्कर्स यूनियन (इंटक) के तत्वावधान में बुधवार अध्यक्ष विनोद कश्यप एवं सचिव ए के सिंह के कुशल नेतृत्व में यूनियन पदाधिकारियों के साथ एनएमडीसी के अध्यक्ष–सह-प्रबंध निदेशक अमिताभ मुखर्जी के नाम कर्मचारियों एवं नगर परिवार के जन उपयोगी कार्यों से संबंधित विभिन्न लंबित मांगों के समाधान हेतु एक विस्तृत, तथ्यपरक, सुव्यवस्थित एवं अत्यंत सम्मानजनक मांग पत्र सौंपा गया।यूनियन ने यह भी रेखांकित किया कि प्रबंधन एवं कर्मचारियों के मध्य सुदृढ़ समन्वय ही एनएमडीसी की प्रगति की आधारशिला है, और इसी पारस्परिक विश्वास एवं सहयोग के बल पर संगठन निरंतर नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा हैं। सौंपे गए पत्र में वेज रिवीजन, एल-1, एल-2 सहित विभिन्न श्रेणियों में आवश्यकतानुसार त्वरित स्थायी भर्ती,ठेका श्रमिक कल्याण – ESIC, फूड कूपन, आवास एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं का समुचित प्रावधान सुनिश्चित करने, LOP व्यवस्था सुधार करने,एरियर्स भुगतान शीघ्र करने,किरंदुल से रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर हेतु नियमित परिवहन सुविधा प्रारंभ करने, पर्यावरण संरक्षण हेतु इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने,ओवरब्रिज सहित लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने,परियोजना अस्पताल में डायलिसिस एवं MRI जैसी उन्नत सेवाएं उपलब्ध कराने जैसे महत्वपूर्ण मांगें शामिल रहीं।

कोनगुड़ में श्रम पंजीयन शिविर का हुआ आयोजन, 29 श्रमिकों का हुआ पंजीयन

कोंडागांव। छत्तीसगढ़ शासन की मंशा के अनुरूप एवं कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना के निर्देशानुसार जिला कोण्डागांव में निर्माण श्रमिकों एवं असंगठित कर्मकारों के पंजीयन, नवीनीकरण तथा विभागीय योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फरसगांव विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत कोनगुड़ में मोबाइल पंजीयन एवं नवीनीकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन कार्यालय श्रम पदाधिकारी, जिला कोण्डागांव द्वारा किया गया, जिसमें कुल 29 श्रमिकों का पंजीयन किया गया, वहीं 02 नवीनीकरण किया गया। इस अवसर पर श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। शिविर में नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, मिनीमाता महतारी जतन योजना, नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभ, पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताया गया। अधिकारियों ने श्रमिकों से अधिक से अधिक संख्या में पंजीयन कराकर योजनाओं का लाभ लेने की अपील की।

गुण्डाधुर महाविद्यालय में पृथ्वी दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम, विद्यार्थियों ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

कोण्डागांव। शासकीय गुण्डाधुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोण्डागांव में पृथ्वी दिवस के अवसर पर भूगोल विभाग द्वारा स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण को केंद्र में रखते हुए विविध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम प्राचार्य डॉ. सरला आत्राम के निर्देशन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ भूगोल विभागाध्यक्ष समलेश पोटाई ने किया, जबकि अध्यक्षता इतिहास विभागाध्यक्ष डॉ. पुरोहित कुमार सोरी ने की। मुख्य अतिथि के रूप में वनस्पति शास्त्र विभागाध्यक्ष शशिभूषण कन्नौजे एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में जन्तु शास्त्र विभागाध्यक्ष शोभा राम यादव उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्राध्यापकगण सहित बी.ए. एवं एम.ए. (भूगोल) के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान पोस्टर मेकिंग, मॉडल प्रदर्शनी, पीपीटी प्रेजेंटेशन, वाद-विवाद और रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने स्वच्छ पर्यावरण, प्लास्टिक मुक्त जीवन, कचरा प्रबंधन और हरित वातावरण जैसे विषयों पर रचनात्मक प्रस्तुतियां दीं। अध्यक्षीय उद्बोधन में डॉ. सोरी ने कहा कि पृथ्वी दिवस पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी समझने का अवसर है। मुख्य अतिथि कन्नौजे ने स्वच्छता को पृथ्वी संरक्षण का सरल उपाय बताते हुए लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। वहीं शोभा राम यादव ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवन की आधारशिला है। प्रतियोगिताओं में रंगोली में निकिता साहू प्रथम, ज्योति मानिकपुरी द्वितीय व दीपिका कुलदीप तृतीय रहीं। मॉडल प्रदर्शनी में तनु नागेश प्रथम, नंदनी देवांगन द्वितीय व भूपेंद्र तृतीय स्थान पर रहे। वाद-विवाद में राजबत्ती मंडावी प्रथम, कुसुम कोर्राम द्वितीय व अमरबत्ती मरकाम तृतीय रहीं।

पोस्टर मेकिंग में पुष्पलता मरकाम प्रथम, भूमिका मंडावी द्वितीय व निहारिका कश्यप तृतीय स्थान पर रहीं। प्रश्न मंच में रेणुका ठाकुर प्रथम, अविता पोटाई द्वितीय व परमेश्वरी तृतीय रहीं। कार्यक्रम के अंत में एम.ए. चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों ने सभी को स्वच्छता एवं पृथ्वी संरक्षण की शपथ दिलाई। मंच संचालन कुसुम पांडे एवं हरिचंद्र नेताम ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन जगतू राम नेताम ने किया।

संक्षिप्त समाचार

ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर फेडरेशन के आह्वान पर जनाक्रोश दिवस मनाया

अंबिकापुर। ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर फेडरेशन के आह्वान पर जनाक्रोश दिवस के तहत फेडरेशन ने प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देते हुए मांग किया है कि 8th वेतन आयोग द्वारा पेंशन संशोधन निर्धारण का लाभ सभी पेंशनर को बिना किसी पक्ष पात के दिया जाए आयोग में सभी पेंशनर को लाभ नहीं दिए जाने का प्रावधान रखा गया है जिस कारण पेंशनरों में असंतोष एवम् आक्रोश है केंद्रीय सरकार के घोषणा का पूरा पूरा लाभ राज्य सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है राज्य सरकार भेदभाव नीति लंबे समय से लागू कर रहा है जो अनुचित एवम् आपत्तिजनक है comutation को राशि की वसूली 11साल में की जाए चार श्रम कानून को वापिस लिया जाए नई शिक्षा नीति वापस ली जाए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए पेंशनरों को कोविड के पूर्व जारी रेल किराया रियायत हवाईजहाज यात्रा की सुविधा बहाल की जाए पेंशनरों की आय को आयकर से पूर्णत: छूट दी जाय अतिरिक्त वेतन वृद्धि लाभ 65वर्ष की उम्र से दिया जाए 80वर्ष उम्र सीमा में संशोधन किया जाए किसानों का msp लागू किया जाए आदि मांगो से संबंधित ज्ञापन देकर सहानुभूति पूर्वक विचार कर निर्णय लिए जाने का अनुरोध किया गया है साथ ही धारा ऊंचास छ को विलोपन एवम् लंबित एरियर्स के भुगतान की मांग की गई है इसकी विज्ञप्ति राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनंत सिन्हा ने जारी की है

राममंदिर के सामने प्लास्टिक दुकान में आगजनी प्रकरण की जांच हेतु संयुक्त दल गठित

अम्बिकापुर। अम्बिकापुर शहर में राममंदिर के सामने स्थित मुकेश प्लास्टिक दुकान में हुई आगजनी की घटना को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त जांच दल का गठन किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सरगुजा द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर सात दिवस के भीतर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 अप्रैल 2026 को उक्त स्थल पर आगजनी की घटना घटित हुई थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक सरगुजा के पत्र के आधार पर पुलिस, जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए जांच दल गठित किया गया है। गठित जांच दल में अनुविभागीय दण्डाधिकारी अम्बिकापुर, नगर पुलिस अधीक्षक अम्बिकापुर, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के प्रतिनिधि, जिला नगर सेना तथा नगर पालिक निगम के कार्यपालन अभियंता को शामिल किया गया है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है कि जांच दल घटना के सभी पहलुओं की विस्तृत जांच कर सात दिवस के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करे, ताकि आवश्यकतानुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

बलरामपुर में अवैध शराब तस्करी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

बलरामपुर। जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफपुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 210 लीटर अंग्रेजी शराब और एक बोलेरो वाहन जब्त किया है। यह शराब मध्य प्रदेश से तस्करी कर लाई जा रही थी। जानकारी के अनुसार, पुलिस चौकी बलंगी अंतर्गत तुंगवा चेक पोस्ट पर नियमित जांच के दौरान संदिग्ध बोलेरो वाहन को रोकने का प्रयास किया गया।

अंबिकापुर में फूटा जन-आक्रोश

महिला आरक्षण के विरोध पर युवा मोर्चा द्वारा निकाला गया शव यात्रा

अंबिकापुर। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल योगराज टिकरिया के आह्वान पर, भाजपा जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया के मार्गदर्शन एवं भाजयुमो जिला अध्यक्ष निशांत सिंह (सोलू) के नेतृत्व में नारी शक्ति के अपमान और विकास विरोधी राजनीति के खिलाफ आम जनता के साथ मातृ शक्ति का भारी रोष देखने को मिला। संसद में महिला आरक्षण को विपक्ष को गठबंधन सरकार द्वारा बाधित किए जाने और विधेयक को गिराने के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा सरगुजा द्वारा गत बुधवार को स्थानीय नागरिकों एवं विभिन्न संगठनों के साथ पी. जी. कॉलेज अंबिकापुर से घड़ी चौक तक एक विशाल 'आक्रोश रैली' निकाला गया, जिसमें विपक्ष के नेताओं का शव यात्रा कर विरोध प्रदर्शन किया गया। विगत दिनों संसद में जिस प्रकार महिला आरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयक को विपक्षी पार्टी के विरोध के चलते गतिरोध का सामना करना पड़ा, उसे लेकर आम जनता एवं नारीशक्ति में गहरा असंतोष है। महिलाओं का कहना है, कि यह कृत्य न केवल महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन है, बल्कि देश की आधी आबादी के सशक्तिकरण के प्रयासों पर आघात है। आक्रोश रैली में विपक्षी नेता राहुल गांधी के साथ सभी विपक्षी पार्टियों का विरोध कर नारे बाजी किया गया एवं स्थानीय घड़ी चौक पर विपक्षी नेताओं का पुतला दहन कर युवा मोर्चा के साथ महिलाओं ने ये संकल्प लिया कि जबतक परिसीमन पश्चात 33% महिला आरक्षण संसद में पास नहीं होगा इनका विरोध प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान पूरे मार्ग में नारीशक्ति एवं युवामोर्चा का उत्साह देखने लायक था। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए कार्यकर्ता महिला आरक्षण के समर्थन में नारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। पुलिस की मौजूदगी में कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने में विनोद हर्ष, अरुणा सिंह, विकास पांडे, निश्छल प्रताप सिंह, प्रिया सिंह, शुभांगी बिहाड़े, मनोज कंसारी, रविकांत उरांव, निरंजन राय, संजीव वर्मा, अभिषेक सिंह देव, जतिन परमार, विकास सोनी, वीर सोनी, रोहित कुशवाहा, प्रियंका चौबे, निरूपा सिंह, दिव्या सिंह सिसोदिया, शालिनी सिंह, आशा शुक्ला, किरण सिंह तोमर, कमलेश्वरी पैकरा, नानमणि पैकरा, सीमा कश्यप, रजनी बिंग, साधना सरकार, अर्चना सिंह, किरण सोनी, नेहा सोनवानी, बबली नेताम, ज्योति, नालिनि पाण्डेय, प्रेमलता गुप्ता, सविता शर्मा, हेमलता शर्मा, विकास शुक्ला, अनीश सिंह, अविनाश मंडल,रजनीत सिंह, शुभम सिंह भदौरिया, आशुमल गर्ग, अनुराग शुक्ला, ओंकारेश्वर सिंह, सौरभ मिश्रा, प्रीतेश दुबे, अभिषेक सिंह, आदित्य गौतम, अभिषेक माथुर, आदित्य पांडे, शैलेन्द्र चौबे, शुभम सोनी, सुधांशु चौबे, आयुष दुबे, विशाल सिंह, अमित अग्रवाल, अभिषेक पावले,रोहन मंडल, किशन उपाध्याय, संजय बेहरा, पारसनाथ यादव, अभिषेक पावले, धनंजय सिंह, धर्मेंद्र गुप्ता, लालू यादव, नार सिंह निखिल मराबी, नीरेंद्र सारथी, रमेश यादव, सहित पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

बिलासपुर रेल्वे स्टेशन में चला किलाबंदी टिकट चेकिंग अभियान

- 301 मामलों में 1 लाख 63 हजार 550 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

बिलासपुर। बिलासपुर मंडल वाणिज्य विभाग द्वारा बिना टिकट यात्रा पर प्रभावी नियंत्रण एवं यात्रियों में वैध टिकट लेकर यात्रा करने के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सघन टिकट जांच अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अनुराग कुमार सिंह के मार्गदर्शन में ट्रेनों तथा स्टेशनों पर टिकट जांच को और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु एक विस्तृत कार्ययोजना के तहत चलाई जा रही है इस अभियान के तहत सहायक वाणिज्य प्रबंधक श्री डी.एस. चौहान के नेतृत्व में आज बिलासपुर स्टेशन तथा गाड़ियों में किलाबंदी टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान में वाणिज्य निरीक्षक, मुख्य टिकट निरीक्षक एवं टीटीई स्टाफ की सक्रिय भागीदारी रही। इस अभियान के अंतर्गत दिनांक 23 अप्रैल, 2026 को बिलासपुर स्टेशन पर किलाबंदी टिकट जांच की गई। इस दौरान कुल 301 मामलों से 1,63,550 रुपये बतौर जुर्माना वसूला गया। इनमें बिना टिकट यात्रा के 235 मामलों से 1,41,670 रुपये, अनियमित टिकट के 49 मामलों से 20,180 रुपये, बिना बुक किए गए लगेज के 16 मामलों से 1,600 रुपये तथा गंदगी फैलाने के 01 मामले से 100 रूपये का जुर्माना शामिल है। यात्रीगण कृपया यात्रा के लिए उचित एवं वैध टिकट लेकर ही यात्रा करें तथा स्टेशन परिसर में प्रवेश से पूर्व प्लेटफार्म टिकट अवश्य खरीदें। रेलगाड़ी राष्ट्रीय संपत्ति है, इसे स्वच्छ एवं सुरक्षित बनाए रखने में रेल प्रशासन का सहयोग करें।

अवैध कोयला खनन के दौरान पत्थर में दबने से ग्रामीण की मौत

- दुर्गंध आने पर घटना की हुई जानकारी
- जेसीबी मशीन से पत्थर को हटवाकर शव निकलवाया बाहर

लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कटकोना और अमेरा खदान के सरहद पर अवैध कोयला खनन के दौरान पत्थर में दबने से ग्रामीण की मौत हो गई है।इधर पुलिस शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सुपुर्द कर मामले की जांच में जुटी है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम कटकोना और अमेरा खदान की सरहद पर 24 अप्रैल दिन शुक्रवार कोसुबह नदी किनारे से अजीब दुर्गंध आने पर ग्रामीणों ने जब जाकर देखा तो पत्थर के नीचे ग्रामीण दबा हुआ था। घटना की सूचना पुलिस को दी गई पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीन के माध्यम से पत्थर को हटवा कर मृतक के शव को बाहर निकलवाया गया और मृतक की पहचान जयप्रकाश पिता सुब्रन ग्राम लोसगी थाना लखनपुर निवासी के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि मृतक प्रतिदिन की भांति 22 अप्रैल दिन बुधवार सुबह कोयला लेने खदान क्षेत्र गया हुआ था कोयला खुदाई करने के दौरान ऊपर से पत्थर गिरने से ग्रामीण दब गया और मौके पर ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई।दुर्गंध आने के बाद ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिली और सूचना लखनपुर पुलिस को दी लखनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा कर परिजनों को सुपुर्द किया है। फिलहाल पुलिस मर्ग कायम करते हुए मामले की जांच में जुटी है।इधर घटना के बाद परिवार जनों में शोक का माहौल व्याप्त है।

गिरसा के आंगनबाड़ी केंद्र का कलेक्टर डॉ कन्नौजे ने किया निरीक्षण

सारंगढ़। कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे ने बुधवार को बिलाईगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत गिरसा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान केंद्र में उन्होंने महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं के लिए लगाए गए ई-केवाईसी कैंप का जायजा लिया।कलेक्टर ने मौके पर मौजूद महिलाओं और संबंधित कर्मचारियों से ई-केवाईसी की प्रगति की जानकारी ली और सभी पात्र हितग्राहियों का जल्द से जल्द ई-केवाईसी पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है और कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से की जा रही है। इसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क न लिया जाए।इस दौरान कलेक्टर ने महिलाओं को महतारी वंदन योजना के लाभों की जानकारी देते हुए समय पर आवश्यक प्रक्रियाएं पूर्ण करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने आगामी जनगणना 2027 के संबंध में भी जागरूक किया। कलेक्टर ने कहा कि वर्तमान में मकान जनगणना का कार्य ऑनलाइन एवं डिजिटल माध्यम से प्रारंभ हो चुका है और इसका पहला चरण संचालित किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने और योजनाओं का लाभ समय पर हितग्राहियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।

मंत्री राजेश अग्रवाल की उपस्थिति में जिला खनिज संस्थान न्यास की शासी परिषद की बैठक संपन्न.....

- डीएमएफतहत स्वीकृत, पूर्ण और प्रगतिरत कार्यों की हुई समीक्षा
- स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पेयजल सहित अन्य कार्यो पर चर्चाकर तैयार की गई कार्ययोजना

अंबिकापुर। पर्यटन संस्कृति धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री श्री राजेश अग्रवाल की उपस्थिति तथा कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला खनिज संस्थान न्यास श्री अजीत वसंत की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला कलेक्टरेट सभाकक्ष में शासी परिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक में लुण्ड्रा विधायक श्री प्रबोध मिंज, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती निरुपा सिंह, एसपी श्री राजेश अग्रवाल, डीएफओ श्री अभिषेक जोगावत सहित शासी परिषद के सभी सदस्य मौजूद रहे। शासी परिषद की बैठक में सीईओ जिला पंचायत एवं सदस्य सचिव जिला खनिज संस्थान न्यास श्री विनय अग्रवाल ने वर्ष 2016-17 से वर्ष 2025-26 तक सेक्टरवार कार्यों की प्रगति की स्थिति की जानकारी दी। जिसमें उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय, कृषि, पशुपालन, महिला एवं बाल कल्याण, स्वच्छता आदि तथा अन्य प्राथमिकता के क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत, पूर्ण और प्रगतिरत कार्यों की जानकारी शामिल रही। बैठक में मंत्री सहित विधायक एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा जिले के विकास हेतु सुझाव साझा किया गया। मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि हमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशुपालन, महिला बाल विकास, स्वच्छता के ऊपर विशेष फोकस, गाइडलाइन के हिसाब से भी इन्हीं के ऊपर ज्यादा खर्च करना है, उसी प्रकार से अनुमोदन भी प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने पूर्व में स्वीकृति कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सुपर 30 कोचिंग में विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने पर जोर दिया जाए। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को जिम्मेदारी के साथ गुणवत्तापूर्ण सभी कार्य को पूर्ण कराने के निर्देश दिए। लुण्ड्रा विधायक श्री प्रबोध मिंज ने कृषि क्षेत्र में विशेष फोकस करने निर्देशित किया।

बिलासपुर ने रचा इतिहास 50,000 से अधिक परिवारों का 'अपना घर' सपना साकार हुआ...

बिलासपुर। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिलासपुर जिले ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए 50,044 परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराए हैं। यह उपलब्धि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), पीएम जन मन योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम है, जिसके माध्यम से जिले के हजारों जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित व सम्मानजनक जीवन की नई शुरुआत मिली है।जिला प्रशासन द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। कुल 781.13 करोड़ रुपये की राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई और कार्यों में तेजी आई। क्षेत्रवार आंकड़ों पर नजर डालें तो मस्तूरी विकासखंड 14,973 आवासों के साथ जिले में शीर्ष पर रहा। इसके बाद बिल्हा में 13,762, कोटा में 11,205 और तखतपुर में 10,104 आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया। यह आंकड़े न केवल प्रशासनिक दक्षता को दर्शाते हैं, बल्कि जमीनी स्तर पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को भी साबित करते हैं। इस सफलता के पीछे 'नारी शक्ति' की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जिले में 113 महिलाओं को 'रानी मिस्त्री' के रूप में प्रशिक्षित कर उन्हें निर्माण कार्य में सक्रिय भागीदारी दी गई, जिससे वे आत्मनिर्भर बनीं। वहीं 331 महिलाओं को 'डीलर दीदी' बनाकर निर्माण सामग्री की आपूर्ति की जिम्मेदारी

सौंपी गई, जिससे स्थानीय स्तर पर संसाधनों की उपलब्धता बढ़ी। इसके अलावा 2,231 महिलाओं को शटरिंग सामग्री किराये पर उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे निर्माण कार्यों में तेजी आई और महिलाओं की आय के नए स्रोत विकसित हुए। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2025-26 तक जिले ने कुल 1,03,873 आवास पूर्ण कर छत्तीसगढ़ में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि जिले की मजबूत कार्ययोजना, सतत मॉनिटरिंग और जनसहभागिता का परिणाम है। इस योजना का मानवीय पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ग्राम डारसागर की झांगली बैगा और ग्राम नेवसा की कैलाशा बाई जैसी हितग्राही, जो वर्षों से कच्चे मकान में कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही थीं, आज पक्के घर में सुरक्षित और सम्मानपूर्वक जीवन जी रही हैं। उनके लिए यह केवल एक मकान नहीं, बल्कि सुरक्षा, आत्मसम्मान और बेहतर भविष्य का प्रतीक है। कलेक्टर संजय कुमार अग्रवाल ने इस उपलब्धि को जिले के लिए गौरवपूर्ण बताते हुए कहा कि ये 50,000 से अधिक घर केवल ईंट और सीमेंट की संरचनाएं नहीं, बल्कि गरीब परिवारों के सम्मान और सुरक्षा की नींव हैं। वहीं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप कुमार अग्रवाल ने कहा कि भविष्य में भी पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता रहेगी।

कलेक्टर ने शहर से बाहर फटाका गोदाम शिफ्ट करने के दिए निर्देश सात दिवस में मांगी जांच रिपोर्ट

अम्बिकापुर। कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने नगर में संचालित फटाका गोदामों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि नगर अम्बिकापुर के सभी फटाका दुकानों के भण्डारण/गोदामों को शहर से बाहर शिफ्ट किया जाए। जारी निर्देशानुसार नगर अम्बिकापुर में कुल 08 स्थाई फटाका लायसेंसधारी एवं 02 फटाका निर्माण के लायसेंसधारी संचालित हैं। इनमें मो0 जुनैद, श्री सतीश कुमार जैन, श्री विनोद कुमार जैन, श्री रोशनलाल गोयल, श्री आशीष कुमार अग्रवाल, श्री अजय कुमार गोयल, श्री गौरीशंकर पाण्डेय, श्री मुकेश कुमार अग्रवाल (दो प्रविष्टियां, जिनमें एक फटाका निर्माण हेतु) तथा श्री मनोज कुमार मारू (फटाका निर्माण हेतु) शामिल हैं। अनुविभागीय दण्डाधिकारी अम्बिकापुर को निर्देशित किया गया है कि संबंधित सभी फटाका गोदामों का निरीक्षण कर निम्न बिन्दुओं पर जांच सुनिश्चित करें— (1) क्या ये सभी गोदाम रिहायसी क्षेत्र में स्थित हैं। (2) क्या गोदाम तक आकस्मिक स्थिति में अग्निशमन वाहन के पहुंचने हेतु पर्याप्त मार्ग उपलब्ध है। (3) क्या वर्तमान में लायसेंस की शर्तों का पालन किया जा रहा है। (4) यदि जांच के दौरान अवैध भण्डारण अथवा घनी आबादी के बीच गोदाम पाए जाते हैं तो वैधानिक कार्यवाही करते हुए उन्हें स्थानांतरित कराया जाए।

जानकी नवमी पर माता सीता की पूजा

वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को माता सीता का प्राकट्य हुआ था। राजा जनक को खेत में हल चलाते समय धरती से पुत्री की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम सीता रखा गया है। इस पर्व को जानकी नवमी भी कहते हैं। इस साल वैशाख शुक्ल नवमी तिथि 2 दिन पड़ने से सीता नवमी मनाने की तारीख को लेकर लोगों में असमंजस है। जानिए सीता नवमी किस तारीख को है और सीता माता की पूजा का शुभ मुहूर्त व विधि।

जानकी नवमी कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार, वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि की शुरुआत 24 अप्रैल 2026 को रात 07 बजकर 21 मिनट पर होगी और इसका समापन अगले दिन यानी 25 अप्रैल 2026 को शाम 06 बजकर 27 मिनट पर होगा। उदयातिथि के अनुसार सीता नवमी पर्व 25 अप्रैल को मनाया जाएगा। सीता नवमी पर पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 10 बजकर 58 मिनट से दोपहर 1 बजकर 34 मिनट तक है।

जानकी नवमी पूजा विधि

जानकी नवमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत-पूजा का संकल्प लें। फिर पूजा स्थल की सफाई करें। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माता सीता और भगवान राम की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। फिर उनका तिलक करें। उन्हें पीले फूल, श्रृंगार की वस्तुएं और भोग अर्पित करें। दीपक जलाएं। 'श्री जानकी रामाभ्यां नमः' मंत्र का 108 बार जप करें। सीता नवमी की कथा का पाठ करें। अंत में आरती करें। पूजा में हुई गलतियों के लिए मन से क्षमा मांगें।

जानकी नवमी व्रत करने का महत्व

जानकी नवमी का व्रत करने से सौभाग्य बढ़ता है। जीवन में सुख-समृद्धि आती है। इस दिन भगवान राम की भी पूजा की जाती है। राम-सीता की पूजा करना जीवन की विघ्न-बाधाओं को दूर करता है। चूंकि सीता माता भूमिपुत्री हैं इसलिए यह दिन धरती माता और प्रकृति के प्रति सम्मान प्रकट करने का भी है।

शादी वाले घर में गलती से भी न रखें ये सामान

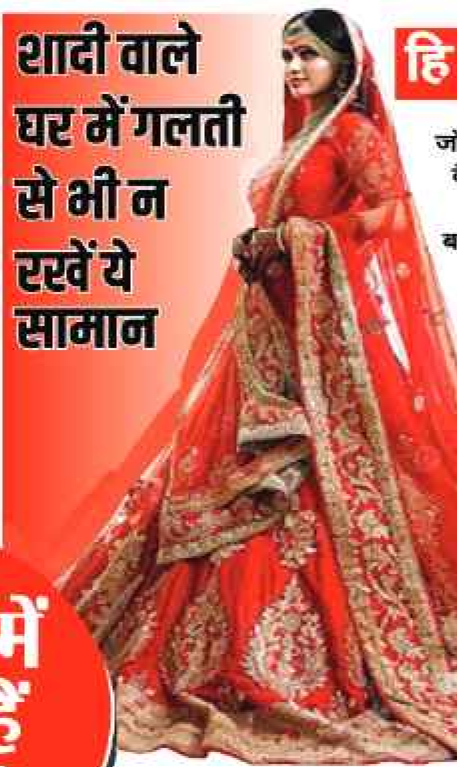

जीवन में आती हैं बाधाएं

हिन्दू धर्म में वास्तु शास्त्र के अनुसार, जिस घर में शादी होने वाली है, वहां सकारात्मक ऊर्जा का होना बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अच्छे कामों में बाधा डालते हैं और कई लोगों के वैवाहिक जीवन में भी बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। शादी के घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए जिस घर में शादी होने वाली है, वहां ऐसी चीजें रखनी चाहिए जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाने के लिए घर के दरवाजे पर हल्दी और चावल से स्वस्तिक बनाया जाता है। हल्दी का प्रयोग शादियों में भी व्यापक रूप से किया जाता है। शाम को विवाह स्थल पर घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। विवाह वाले घर में घी या सरसों का दीपक जलाने से उस घर में सकारात्मकता बनी रहेगी।

इसके साथ ही विवाह वाले घर में वाद-विवाद और मतभेद से बचें ताकि घर का माहौल खराब न हो। इसके अलावा तुलसी, मनी प्लांट, पीस लिली जैसे पौधे घर का माहौल सकारात्मक बनाए रखते हैं। इसी तरह वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस घर में शादी होनी है, वहां कुछ चीजें नहीं रखनी चाहिए, वरना वास्तु दोष उत्पन्न होने का खतरा हो सकता है। आइए जानें शादी वाले घर में कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए।

इन बातों का रखें ध्यान

वास्तु शास्त्र के अनुसार, हर चीज किसी न किसी ऊर्जा से जुड़ी होती है। कौन सी ऊर्जा का उपयोग कब किया जाए, इसका भी समय रहते निर्णय लिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, युद्ध, युद्धभूमि या महाभारत से संबंधित तस्वीरें विवाह घर में नहीं लगानी चाहिए। इससे घरेलू कलह और वाद-विवाद बढ़ सकता है। इसके साथ ही घर का माहौल भी नकारात्मक नहीं होता। जिस घर में शादी होनी है, वहां कांटेदार या नुकीले पौधे नहीं रखने चाहिए। विशेषकर जिस स्थान या कमरे में आप हल्दी, मेहंदी, कत्था आदि अनुष्ठान करने जा रहे हैं, वहां कांटेदार या अन्य पौधे न रखें। ऐसा करने से वास्तु संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।

दक्षिण दिशा का महत्व

दक्षिण दिशा को यमराज और पितरों की दिशा कहा जाता है, इसलिए दक्षिण दिशा में दर्पण नहीं लगाना चाहिए. इसके कारण घर के लोगों के मन में नकारात्मक भावनाएं घर कर सकती हैं. दक्षिण दिशा में दर्पण लगाने से कई प्रकार के वास्तु दोष उत्पन्न हो सकते हैं. जिस घर में शादी होनी है, वहां से सूखे फूल या सूखे फूलों की माला हटा देनी चाहिए. अक्सर, मृतक रिश्तेदारों की तस्वीरें या प्रार्थना कक्ष में रखी देवी-देवताओं की मूर्तियों पर फूलों की मालाएं कई दिनों तक लटकी रहती हैं.

मटर पनीर कोफ्ता

कोफ्ते कई तरह से बनाए जाते हैं। अगर आप रोजाना एक जैसा खाना खाकर बोर हो गए हैं तो आप मटर पनीर कोफ्ता बना सकते हैं। रोटी-पराठे के साथ ये कोफ्ते स्वाद में काफी अच्छे लगते हैं। अगर आप यहां बताई रेसिपी से कोफ्ते बना रही हैं तो कम समय और सामान में इन्हें बनाकर तैयार कर पाएंगी। यहां देखिए मटर पनीर के कोफ्ते बनाने का तरीका-

आवश्यक सामग्री

एक कप पनीर,- एक कप मटर ,- एक से दो मिर्च,- एक छोटा टुकड़ा अदरक,- 4 से 5 लहसुन की कलियां,- 2.5 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर,- एक छोटा चम्मच कसूरी मेथी,- स्वादानुसार नमक,- धनिया पत्ती,- तलने के लिए तेल, - आधा कप पानी, दो बड़े चम्मच क्रीम, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला

बनाने की विधि

मटर पनीर कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले कोफ्ते तैयार करें। इसके लिए मटर को हरी मिर्च, अदरक और लहसुन के साथ पीस लें। फिर पनीर को कद्दूकस करें और इसमें मटर के पेस्ट, कसूरी मेथी और नमक को मिला दें। अच्छे से मैश करें और फिर इस बैटर से छोटे-छोटे बॉल्स तैयार कर लें। अब तेल अच्छे से गर्म करें और फिर इसमें सभी कोफ्तों को गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लें। अब सभी कोफ्ते एक तरफ रखें और ग्रेवी तैयार करें। ग्रेवी बनाने के लिए एक ब्लेंडर में प्याज के साथ एक मीडियम साइज प्याज, दही, पुदीने की पत्तियां, धनिया पत्ती, काजू, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को ब्लेंड कर लें। अब एक कढ़ाई मे तेल गर्म करें और फिर इसमें जीरा, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची डालें। फिर , हल्दी, कश्मीरी मिर्च, धनिया पाउडर डालें और पानी की कुछ बूंदे भी इसमें मिला दें। फिर मसाला पकने के बाद इसमें प्याज के पेस्ट को डालें और अच्छे से भूनें। नमक और चीनी के कुछ दाने डालें। अच्छे से मिक्स करें और जरूरत के मुताबिक पानी डालें। गाढ़ापन आने के बाद दो बड़े चम्मच क्रीम और गरम मसाला डालें। फिर कोफ्ते डालें और ग्रेवी के साथ मिक्स होने दें। आंच बंद करें और सर्व करें।

गर्मी के मौसम में परफ्यूम लगाने के टिप्स

गर्मी के दिनों में पसीना आने की दिक्कत बहुत ज्यादा होती है। जिसकी वजह से कुछ लोगों के शरीर से अजीब गंध आने लगती है। इस गंध से निपटने के लिए लोग परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं। थोड़े से परफ्यूम को छिड़कने के बाद न सिर्फ आप महकने लगते है बल्कि इससे आपका मूड और भी बेहतर हो जाता है। हालांकि, कुछ लोगों की शिकायत ये रहती है कि परफ्यूम की खुशबू भी उनके शरीर में लंबे समय तक नहीं टिकती। गर्मी के मौसम में परफ्यूम कैसे लगाएं ताकी खुशबू लंबे समय तक टिकी रहे। गर्मी में परफ्यूम लगाने की टिप्स..

पल्स पॉइंट्स पर लगाएं

गर्मी के मौसम मे कलाई, गर्दन और कान के पीछे परफ्यूम लगाएं। शरीर के इन हिस्सों पर खुशबू ज्यादा देर तक बनी रहती है।

हल्का स्प्रे करें

परफ्यूम लगाने के लिए आपको बस हल्के स्प्रेज की जरूरत होती है। गंध से बचने के लिए इसे बहुत ज्यादा लगाने से बचें।

रगड़ें नही

ज्यदातर लोग परफ्यूम स्प्रे करने के बाद अपनी कलाइयों को आपस में रगड़ने लगते हैं। आपको ऐसा करने से बचना चाहिए। क्योंकि इससे खुशबू बदल सकती है।

नहाने के बाद लगाएं

थोड़ी नम त्वचा पर परफ्यूम लगाने से खुशबू लंबे समय तक टिक सकती है। इसलिए नहाने के बाद इसे लगाएं। हालांकि, सेंसेटिव हिस्सों पर लगाने से बचें।

बालों और कपड़ों लगाएं

अगर आप चाहते हैं कि खुशबू लंबे समय तक बनी रहे तो परफ्यूम को बालों या कपड़ो पर स्प्रे कर सकते हैं।

लेयरिंग करें

परफ्यूम की खुशबू को लंबे समय टिकाए रखने के लिए अपने परफ्यूम से मैच करती खुशबू वाले बॉडी लोशन या ऑयल की लेयरिंग करें।

गर्मियों में जरूर पीना चाहिए सौंफ का पानी

गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। ये मौसम अपने साथ कई परेशानियां लेकर आता है। इस दौरान सेहत से जुड़ी कई मौसमी बीमारियां भी लोगों को घेर लेती हैं। अस्पतालों में भी मरीजों की भीड़ देखने को मलिती है। इस बार मौसम वभिाग ने भीषण गर्मी पड़ने की चेतावनी जारी की है। ऐसे में सेहत का डबल ख्याल रखना होगा। इस मौसम में डिहाइड्रेशन, लू और पाचन की समस्याएं सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। तपती गर्मी में पसीना ज्यादा आता है जिसकी वजह से बॉडी में पानी की कमी होने लगती है।

गर्मी में बॉडी में पानी की कमी को पूरा करने के लिए हम मौसमी फल, हरी सब्जयों को अपनी डाइट में शामलि करते हैं जनिमें पानी की मात्रा ज्यादा पाई जाती हो। ऐसे में आपके कचिन में मौजूद कुछ मसाले भी आपको हाइड्रेट रखने और आपकी बॉडी को ठंडा रखने में मदद कर सकते हैं। हम सौंफ की बात कर रहे हैं। गर्मियों में सौंफ का पानी कसिी वरदान से कम नहीं होता है।

शरीर को पहुंचाए ठंडक

सौंफ में नेचुरल कूलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। इसका पानी पीने से शरीर की गर्मी कम होती है और लू से बचाव होता है। खासकर तेज धूप में बाहर निकलने से पहले सौंफ का पानी पीना चाहिए।

डाइजेशन सुधारे

गर्मी में अक्सर एसडिटी, गैस, कब्ज और पेट दर्द जैसी समस्याएं हो जाती है। सौंफ का पानी इन समस्याओं को दूर करने मे मदद करता है। इसमें मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सिडेंट्स पाचन क्रिया को बेहतर बनाते है और पेट को हल्का रखते है।

बॉडी को करे डिटॉक्स

सौंफ का पानी पीने से शरीर से toxins को बाहर निकालने मे मदद मलिती है। यह लिवर और किडनी की सफाई करता है, जिससे त्वचा भी साफ और चमकदार बनी रहती है।

वेट लॉस में भी फायदेमंद

अगर आप भी अपना वजन तेजी से कम करना चाहते हैं तो आपको गर्मियों मे सौंफ का पानी जरूर पीना चाहिए। यह मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और भूख को कंट्रोल करता है।

त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद

सौंफ मे विटामिन C, एंटीऑक्सिडेंट और मिनरल्स पाए जाते है। ये त्वचा को ग्लोइंग बनाते है। बालों को भी जड़ से मजबूत करते हैं।

दिल की सेहत का रखे ख्याल

सौंफ में फाइबर, पोटैशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। ये सभी दिल की सेहत के लिए जरूरी होते हैं। इसका पानी पीने से दिल से संबंधति बीमारियों का खतरा कम होता है।

कैसे बनाएं सौंफ का पानी?

एक चम्मच सौंफ को रात भर के लिए एक गिलास पानी में भिगो दें। सुबह उठकर इस पानी को छान लें और खाली पेट पिएं। आप चाहें तो इसे हल्का गुनगुना भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा शहद और नींबू भी मिला सकते हैं।

इम्यून सिस्टम की मजबूती के लिए अपनाएं ये टिप्स

लगातार बढ़ती गर्मी की वजह से हर कोई परेशान है। गर्म हवाओं और चिलचिलाती धूप की वजह से लोगों को तरह-तरह की हेल्थ प्रॉब्लम होने लगती हैं। ज्यादातर लोग इस समय पर कमजोरी और थकान महसूस करते हैं। इसके अलावा लु,डिहाइड्रेशन, सिरदर्द जैसी समस्याओं का गर्मी में होना काफी कॉमन है। गर्मियों में भी आप बीमार न पड़े इसके लिए इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखना जरूरी है। यहां हम गर्मियों में इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के कुछ टिप्स बता रहे हैं, जानिए।

1) डायट में करें कुछ जरूरी बदलाव करें

गर्मियों में इम्युनिटी बूस्ट करने के लिए फल और सब्जियों को खाएं। आप बैरीज, खट्टे फल, कीवी, सेब, लाल अंगूर, प्याज जैसी फलों और सब्जियों की मे विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट के अच्छी मात्रा होती है, जो इम्यून सिस्टम को स्पोर्ट करते हैं। ताजा लहसुन इम्यूनिटी को बढ़ावा देने मे फायदेमंद होता है, हालांकि गर्मी में इसकी कम मात्रा ही खाएं। इसके अलावा शिमला मिर्च और ब्रोकली विटामिन सी से भरपूर होते है, जो इम्यून हेल्थ के लिए एक जरूरी पोषक तत्व है। इसके अलावा दही, ग्रीन टी, हल्दी और पत्तेदार साग को भी डायट मे शामिल करें।

2) नींद पर ध्यान दें

क्वालिटी स्लीप पर ध्यान देने से आपके शरीर को रिपेयर करने मे मदद मिलती है। अच्छी और गहरी नींद शरीर के इम्यून सेल्स को फिर से भरने और एक्टिव करने मे मदद मिलती है। नींद मजबूत इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी है।

3) हैवी खाने से बचें

गर्मी के मौसम मे पाचन धीमा पड़ जाता है। ऐसे मे हैवी खाना खाने से पाचन-तंत्र पर दबाव पड़ता है। इसलिए गर्मी के मौसम में हैवी खाना खाने से बचना चाहिए। हेल्दी और हल्का खाना खाने से इम्युनिटी बेहतर बनी रहेगी और आप हेल्दी भी महसूस करेंगे।

4) विटामिन डी है जरूरी

विटामिन डी इम्यून सिस्टम के कामकाज मे जरूरी होता है। गर्मी के मौसम में ज्यादातर लोग धूप सेकने से बचते है हालांकि इस मौसम मे भी आपको पर्याप्त धूप की जरूरत होती है। सुबह की पहली धूप कुछ देर के लिए लें। विटामिन डी बहुत कम हो तो एक्सपर्ट की सलाह पर सप्लीमेंट ले सकते हैं।

फिटनेस के लिए रोजाना एक्सरसाइज की जरूरत

फिट और हेल्दी रहने के लिए रोजाना एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी है। अक्सर लोगों के जेहन में सवाल आता है कि रोजाना कितने देर और कितने समय के लिए वर्कआउट करना चाहिए। क्या जिम या कार्डियों करना चाहिए। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि हेल्दी रहने के लिए रोजाना कम से कम 30 से 45 मिनट तक एक्सरसाइज करनी चाहिए। जानते हैं फिट रहने के लिए रोजाना कितनी देर एक्सरसाइज करनी चाहिए।

कार्डियो एक्सरसाइज क्या होती है

अक्सर कार्डियों का नाम सुनते हैं लोगों के जेहन मे जिम की तस्वीर बन जाती है। कार्डियों एक्सरसाइज करने लिए जिम की जरूरत नही है इसे आप खुद भी कर सकते हैं। दरअसल कार्डियों एक्सरसाइज मे तेज चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना या रस्सी कूदना है। कार्डियों एक्सरसाइज करने से कैलोरी तेजी से बर्न होती है। अगर आप वजन तेजी से कम करना चाहते हैं तो रोजाना कार्डियों कर सकते है।

जिम वर्कआउट

जिम में ज्यादातर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर फोकस किया जाता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से मांसपेशियां मजबूत होती है। जिम में जाकर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है वही शरीर टोन होता है। अगर आप बॉडी टोन करना चाहते है तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर ध्यान दें।

क्या है ज्यादा बेहतर

अच्छी फिटनेस के लिए दोनों ही एक्सरसाइज बेहद जरूरी है। बॉडी को फिट रखने के लिए आप कार्डियो के साथ-साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। आप हफ्ते में 3 दिन कार्डियो और 2 से 3 दिन वेट ट्रेनिंग कर सकते है। इससे बॉडी फिट रहेगी वही वजन भी कंट्रोल रहेगा।

स्ट्रेचिंग और योग

स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अलावा योग पर भी ध्यान देना चाहिए। स्ट्रेचिंग और योग करने से शरीर लचीला रहता है। जो कि शरीर को चोट लगाने से बचाते है। फिट रहने के लिए रोजाना एक्सरसाइज करना चाहिए। भले ही आप 20 मिनट एक्सरसाइज करें लेकिन रोज करें। एक्सरसाइज करने से फिटनेस नही आती है। एक्सरसाइज के साथ-साथ सही खान-पान और पर्याप्त नींद बेहद जरूरी है।

जाम सीवरेज से लोग परेशान, नई लाइन की मांग, आबादी भूमि का पट्टा नहीं मिलने पर कलेक्टर से लगाई गुहार, जनदर्शन में प्राप्त हुए 120 आवेदन

भारत माला सिक्सलेन सड़क से 100 किसान परेशान, खेत तक पहुंचना हुआ मुश्किल

दुर्ग। जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे जनसामान्य लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने को कहा। जनदर्शन में अपर कलेक्टर विरेन्द सिंह एवं डिप्टी कलेक्टर उत्तम ध्रुव भी उपस्थित थे। जनदर्शन में अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन कराने, सीसी रोड निर्माण, ऋण पुस्तिका सुधार, आर्थिक सहायता राशि दिलाने सहित विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से संबंधित 120 आवेदन प्राप्त हुए। इसी कड़ी में गोड़पेन्ड्री के किसानों ने पुल निर्माण कराने

की मांग की। किसानों ने बताया कि गोड़पेन्ड्री में भारत माला परियोजना के तहत बन रही सिक्सलेन सड़क के कारण करीब 100 किसानों को अपने खेतों तक पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क खेतों के बीच से गुजरने के कारण सीधा रास्ता बंद हो गया है। किसानों को अब अपने खेत तक पहुंचने के लिए करीब 3 किलोमीटर दूर मानिकचौरी और अन्य मार्गों से होकर जाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क के दोनों ओर की जा रही घेराबंदी से समस्या और गंभीर हो जाएगी और खेती किसानी प्रभावित होगा। गांव के उत्तरी हिस्से में पहले से पत्थर खदान होने के कारण खेती योग्य जमीन कम बची है और जो कृषि योग्य भूमि बचा है वहां पहुंचने में किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने ग्राम छाटा और मानिकचौरी के बीच अंडरपास/पुलिया निर्माण की मांग की है, ताकि खेतों तक आवागमन आसान हो सके। इस पर कलेक्टर ने एनएच एवं एसडीओ पाटन को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।

मदर टेरेसा वार्डवासियों ने गटर पाइपलाइन के जाम होने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि मदरटेरेसा नगर के वार्ड क्रमांक 31 में गटर पाइपलाइन बार-बार जाम होने से वार्डवासी परेशान हैं। गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है, जिससे दुर्गंध और मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि नगर निगम में इसकी शिकायत की गई थी लेकिन स्थायी समाधान नहीं हुआ है। सफाई के बाद भी गटर जल्द ही फिर जाम हो जाता है। उन्होंने पुरानी पाइपलाइन को बदलकर नई सीवरेज लाइन निर्माण कराने की मांग की। इस पर कलेक्टर ने नगर निगम भिलाई को निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। ग्राम हनोदा निवासी ने आबादी भूमि का पट्टा नहीं मिलने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि उनका कच्चा मकान 1980 से पहले बना था, जो अब क्षतिग्रस्त हो चुका है। वर्ष 2017 में सर्वे के बाद गांव के अन्य लोगों को पट्टा मिल गया, लेकिन उन्हें अब तक वंचित रखा गया है। पड़ोसियों द्वारा मेरा रास्ता बाधित कर अनावश्यक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। इस संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत के बावजूद समाधान नहीं हुआ है। इस पर कलेक्टर ने तहसीलदार दुर्ग को परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

मंडी बोर्ड उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के लिए अभ्यर्थियों के लिए दिशा-निर्देश एवं महत्वपूर्ण सूचना

दुर्ग। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड के अंतर्गत उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2026 का आयोजन रविवार, 26 अप्रैल 2026 को किया जा रहा है। इस परीक्षा में कुल 38,937 अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिसके लिए दुर्ग जिले में 123 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा का समय प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक निर्धारित है। अभ्यर्थियों की सुविधा और सुचारू संचालन के लिए नोडल अधिकारी द्वारा विशेष निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत परीक्षार्थियों को परीक्षा के एक दिन पूर्व अपने केंद्र का अवलोकन करने की सलाह दी गई है। परीक्षा दिवस पर अभ्यर्थियों को कम से कम 2 घंटे पूर्व पहुंचना अनिवार्य है ताकि उनके फोटो युक्त मूल पहचान पत्र का सत्यापन और सुरक्षा जांच की जा सके। विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार प्रातः 9:30 बजे बंद कर दिया जाएगा, जिसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा के दौरान अनुशासन और शुचिता बनाए रखने के लिए परीक्षार्थियों को हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े और फुटवियर के रूप में चप्पल पहनकर आना होगा। गहरे रंग जैसे काले, नीले, हरे, जामुनी, मैरून और चॉकलेटी कपड़ों का उपयोग पूर्णतः वर्जित है। जो अभ्यर्थी धार्मिक या सांस्कृतिक पोशाक पहनकर आएंगे, उन्हें सामान्य समय से पहले केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा और अतिरिक्त सुरक्षा जांच के बाद ही अनुमति दी जाएगी।

जिलों में उपलब्ध पाण्डुलिपियों की व्यवस्थित पहचान कर किया जाएगा सूचीकरण

प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण व डिजिटलीकरण की दिशा में कदम

दुर्ग। ज्ञान भारतम् पाण्डुलिपि सर्वेक्षण अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मुख्य सचिव विकासशील ने वीडियो कॉन्फ्रें सिंग के माध्यम से सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि जिलों में उपलब्ध पाण्डुलिपियों की व्यवस्थित पहचान कर उनका सूचीकरण सुनिश्चित किया जाए। मुख्य सचिव ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य सभी जिलों में पाण्डुलिपियों का समयबद्ध एवं व्यवस्थित सर्वेक्षण करना है। इसके अंतर्गत संस्थागत और निजी संग्रहों में उपलब्ध पाण्डुलिपियों की पहचान, प्रलेखन और सूचीकरण किया जाएगा। साथ ही उनके डिजिटलीकरण एवं संरक्षण की दिशा में भी कार्य किया जाएगा, ताकि एक पाण्डुलिपि डेटाबेस तैयार हो सके। उन्होंने बताया कि पाण्डुलिपि वह मूल हस्तलिखित दस्तावेज या रचना होती है, जो छपाई के आविष्कार से पहले कागज, ताड़पत्र, भोजपत्र, धातु, कपड़े या चमड़े पर लिखी जाती थी। ये पाण्डुलिपियां इतिहास, साहित्य, धर्म, विज्ञान, गणित, ज्योतिष और चिकित्सा जैसे विषयों के प्राचीन ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। मुख्य सचिव ने जानकारी दी कि 12 सितम्बर 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा ज्ञान भारतम् वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। उन्होंने सभी कलेक्टरों को कार्ययोजना बनाकर अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। जिलों में मास्टर ट्रेनर तथा ग्राम एवं क्षेत्र स्तर पर सर्वेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। सर्वेक्षण कार्य 16 मार्च से 15 जून तक तीन माह की अवधि में पूरा किया जाएगा। जिला कलेक्टर को जिले के अंतर्गत पाण्डुलिपि संग्रह केन्द्रों संस्कृत महाविद्यालय, पाठशालाएं, निजी/ सरकारी पुस्तकालय, संग्रहालय, शिक्षण एवं शोध संस्थान, मंदिर, मठ, आश्रम, गुरूकुल, ट्रस्ट आदि तथा इसी प्रकार निजी संग्रहकर्ता, पुरोहित, धर्माचार्य, ज्योतिषाचार्य, संस्कृत एवं प्राचीन भाषाओं के विद्वानों आदि के संग्रह में उपलब्ध पाण्डुलिपियों का चिन्हांकन एवं सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए।

जैविक खाद के उपयोग और मिलेट्स फसलों की पैदावारी को दें बढ़ावा : संभाग आयुक्त राठौर

संभाग आयुक्त ने ली संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक

दुर्ग। संभाग आयुक्त एस.एन. राठौर ने कहा कि संभाग अंतर्गत फसलों की पैदावारी बढ़ाने हेतु जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। इसी प्रकार मिलेट्स फसलों जैसे ज्वार, बाजरा, रागी आदि की पैदावारी के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर इनके प्रोसेसिंग एवं मार्केटिंग पर भी कृषि विभाग द्वारा आवश्यक पहल की जाए। बालोद स्थित मां दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाने में गन्ने की आपूर्ति हेतु गन्ने के फसल की पैदावारी हेतु दुर्ग जिले के किसानों को भी अनुदान राशि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। संभाग मुख्यालय दुर्ग स्थित कृषि विभाग के प्रशिक्षण केन्द्र भवन का सदुपयोग हेतु कृषकों का प्रशिक्षण एवं भ्रमण आदि होते रहना चाहिए। उक्त भवन अन्य विभागों के प्रशिक्षण हेतु भी निर्धारित दर पर उपलब्ध कराई जाए। संभाग आयुक्त राठौर आज संभागीय कार्यालय के सभाकक्ष में संभाग स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में संयुक्त संचालक कृषि को उक्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा 20 अप्रैल से 15 जून 2026 तक स्कूलों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है। संभाग अंतर्गत सभी शासकीय-अशासकीय स्कूलों में आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने संयुक्त संचालक शिक्षा को निर्देशित किया कि बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए ग्रीष्मकालीन अवकाश में समर कैम्प आदि का आयोजन स्कूल प्रबंधन द्वारा नहीं कराये जाए। संभाग आयुक्त राठौर ने सभी कार्यालयों में फाइल मूवमेंट ई-ऑफिस प्रक्रिया के तहत और अधिकारी/कर्मचारियों की निर्धारित समय पर उपस्थिति हेतु बायोमेट्रिक प्रक्रिया अपनाने की जानकारी ली। संभाग आयुक्त राठौर ने अधिकारियों को अवगत कराया कि शासन द्वारा आगामी 1 मई से 10 जून 2026 तक सुशासन तिहार 2026 संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक 15-20 ग्राम पंचायतों के समूह पर जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री, मंत्रीगण एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विकास कार्यों का औचक निरीक्षण पश्चात् जिला मुख्यालयों में समीक्षा बैठक आयोजित किए जाएंगे।

संभाग आयुक्त राठौर ने सभी संभागीय अधिकारियों को सुशासन तिहार हेतु विभागीय तैयारियां करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी कार्यालयों के चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों हेतु ड्रेस कोड पर जोर देते हुए अधिकारियों को गंभीरता से ध्यान देने के निर्देश दिए। संभाग आयुक्त ने शासकीय सीसीएम कॉलेज कचांदुर में पीडब्ल्यूडी एवं विद्युत यांत्रिकी द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों की जानकारी ली एवं अधिकारियों को प्राथमिकता के साथ कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। बैठक में उपायुक्त (राजस्व) पदुमलाल यादव और उपायुक्त (विकास) संतोष ठाकुर एवं समस्त विभाग के संभाग स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

जगतगुरु शंकराचार्य जयंती उत्सव का आयोजन 26 अप्रैल को शहीद स्मारक भवन रायपुर में

छत्तीसगढ़ सनातन दसनाम गोस्वामी समाज का भव्य आयोजन

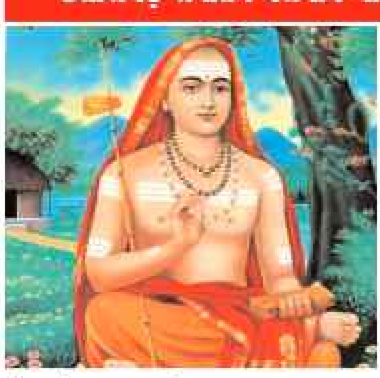

भिलाई नगर। छत्तीसगढ़ सनातन दसनाम गोस्वामी समाज पंजीयन क्रमांक 1657 द्वारा 26 अप्रैल दिन रविवार को भगवान श्री आद्य जगतगुरु शंकराचार्य जयंती उत्सव का आयोजन शहीद स्मारक भवन जय स्तंभ चौक के पास रायपुर में किया जा रहा है।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के उपमुख्यमंत्री अरुण साव,अति विशिष्ट अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, विशिष्ट अतिथि राजेश मूणत विधायक रायपुर पश्चिम,विशिष्ट अतिथि श्रीमती मीनल चौबे महापौर रायपुर, विशिष्ट अतिथि महंत डॉक्टर रामसुंदर दास महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर दूधाधारी मठ रायपुर उपस्थित रहेंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री श्री 1008 महंत विवेक गिरी थानापति महाराज गौरकापा आश्रम करेंगे। यह जानकारी देते हुए गोस्वामी समाज के प्रांतीय अध्यक्ष मोहनपुरी गोस्वामी ने बताया कि जगतगुरु शंकराचार्य जयंती उत्सव पर प्रातः 10:00 बजे से भव्य शोभा यात्रा कार्यक्रम परिसर से निकलकर शहर के कुछ प्रमुख मार्गों में जय घोष करते हुए वापस आने के बाद मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की जाएगी। समाज के महंतों,संस्थापक व संरक्षकों द्वारा श्री आद्य जगतगुरु शंकराचार्य पर केंद्रित व्याख्यान पर संबोधित करेंगे।अतिथियों के आगमन पर उनका स्वागत एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट परिणाम लाने वाले छात्र-छात्राओं का प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम होगा। गोस्वामी समाज के दुर्ग जिला अध्यक्ष दीपक बन गोस्वामी सहित अन्य पदाधिकारियो ने जयंती समारोह में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है।

कन्हापुरी सीमांकन में पहुंचे कलेक्टर, पेंडिंग प्रकरणों के लिए 30 अप्रैल तक अल्टीमेटम्

नए -पुराने सभी राजस्व संबंधित आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण के निर्देश

राजनांदगांव। सीमांकन के नए और पुराने प्रकरणों को निपटाने के लिए 30 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया गया है। इसका असर ऐसा है कि पिछले सप्ताहभर में 150 सीमांकन प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। गुरूवार को खुद कलेक्टर जितेंद्र यादव शहर के कन्हारपुरी वार्ड पहुंचे, जहां सीमांकन का कार्य चल रहा था। यहां उन्होंने किसानों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना - कलेक्टर ने सीमांकन कार्य को सुबह या शाम के समय करने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को गर्मी से राहत मिल सके। उन्होंने अधिकारी-कर्मचारियों को निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर ने किसानों से आवेदन की स्थिति, जमीन का रकबा और लंबित मामलों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि नए और पुराने सभी आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण होना चाहिए। उन्होंने

अधिकारियों को निर्देशित किया कि विवादित प्रकरणों का सीमांकन कर रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत करें। ताकि आगे आवश्यक कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि किसी भी कर्मचारी द्वारा अवैध मांग या प्रलोभन की स्थिति में तत्काल शिकायत कर सकते हैं, ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

शासकीय भूमि पर कब्जा हटाने के दिए निर्देश

कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के एक प्रकरण में संबंधित किसान को 15 दिवस के भीतर कब्जा हटाने के निर्देश दिए।ग्राम कन्हारपुरी के किसान वीरेन्द्र चंद्राकर ने कहा कि उनके 2 एकड़ 50 डिसमील जमीन का सीमांकन किया गया है। उन्होंने सीमांकन के लिए तहसीलदार कार्यालय में आवेदन किया था। राजस्व अधिकारियों और आसपास के किसानों की उपस्थिति में सीमांकन कार्य पारदर्शी तरीके से नापजोख कर किया गया है। इसके साथ ही दो अन्य आवेदक किसान घनश्याम निर्मलकर और निर्मलकर के जमीन का भी सीमांकन किया गया है। कलेक्टर ने कहा कि सभी किसान नियमों का पालन करें, जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो और गांव में सौहार्द बना रहे।

अग्निवीर भर्ती की लिखित परीक्षा हेतु दुर्ग में मिलेगा नि:शुल्क प्रशिक्षण

दुर्ग। भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया 2027 के अंतर्गत पंजीकृत युवाओं के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा (सी.ई.ई.) का आयोजन 1 जून 2026 से 15 जून 2026 के मध्य होना संभावित है। परीक्षार्थियों की बेहतर तैयारी के लिए जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र दुर्ग द्वारा नि:शुल्क परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण आगामी 4 मई 2026 से 3 जून 2026 तक प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। अग्निवीर भर्ती 2026-27 के लिए आवेदन कर चुके इच्छुक अभ्यर्थी इस प्रशिक्षण का लाभ उठाने के लिए रोजगार विभाग के आधिकारिक पोर्टल erojgar.cg.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, विस्तृत जानकारी के लिए आवेदक जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र से ई-मेल ddirempdurgfiyv@gmail.com के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

उप निर्वाचन हेतु जिला स्तरीय शिकायत सेल का गठन

दुर्ग। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में नगर पालिकाओं एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के आगामी उप निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली तैयार/पुनरीक्षण का कार्य जिले में प्रभावशील है। नगरीय निकाय व त्रि-स्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन होना प्रस्तावित है। आगामी निर्वाचन से संबंधित शिकायत पर त्वरित कार्यवाही के लिए जिला स्तरीय शिकायत सेल का गठन किया गया है। यह शिकायत सेल भू-अभिलेख कक्ष क्रमांक 21 में संचालित होगा। इसके संचालन हेतु विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी उनके पूर्व दायित्वों के साथ अतिरिक्त रूप से लगाई गई है। शिकायत सेल में अधीक्षक भू-अभिलेख सुरेखा राजपूत मोबाइल नंबर 8359809792 को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनके साथ सहायक प्रभारी अजय मेरावी (सहायक अधीक्षक) 7987028422 जिम्मेदारी निभाएंगे। इसके अलावा श्रीमती उज्जवला ध्रुव (सहायक ग्रेड-02), सुसाधना वर्मा (कम्प्यूटर ऑपरेटर) तथा राहुल यादव (भृत्य) की ड्यूटी लगाई गई है, जो विभिन्न सहायक कार्यों का निर्वहन करेंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सिंह के आदेशानुसार यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। शिकायत सेल में लगाए गए कर्मचारी प्रभारी अधिकारी के मार्गदर्शन में कार्य संपादित करेंगे।

नगरपालिका उप-निर्वाचन 2026 हेतु भिलाई और रिसाली के लिए रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त

दुर्ग। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभिजीत सिंह ने जिले में होने वाले नगरपालिका उप-निर्वाचन 2026 के लिए रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की है। छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह नियुक्तियाँ भिलाई और रिसाली नगर पालिक निगम के रिक्त वार्डों में चुनाव संपन्न कराने हेतु की गई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड क्रमांक 01 (जुनवानी) के लिए नगर निगम दुर्ग के आयुक्त सुमित अग्रवाल (आईएएस) को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। उनकी सहायता के लिए नगर निगम दुर्ग के उपायुक्त मोहेन्द्र साहू को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी प्रकार, नगर पालिक निगम रिसाली के वार्ड क्रमांक 02 एवं 39 के लिए नगर निगम भिलाई के आयुक्त राजीव पाण्डेय को रिटर्निंग ऑफिसर और उपायुक्त नरेन्द्र बंजारे को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर पदाभिहित किया गया है। यह आदेश तत्कालशील हो गया है। निर्वाचन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित ढंग से पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक तैयारियाँ शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।

नगर निगम भिलाई ने चलाया जल शुद्धिकरण अभियान

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के जोन-2 वैशाली नगर अंतर्गत वार्ड क्रमांक 24 हाउसिंग बोर्ड स्थित फौजी नगर क्षेत्र में जल शुद्धिकरण को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत गणेश मंच एवं शीतला मंदिर मोहल्ले के कुओं में ब्लीचिंग पाउडर का घोल डालकर पानी को शुद्ध किया जा रहा है। विभागीय टीम द्वारा क्षेत्र के लगभग 125 घरों का सर्वेक्षण किया गयाए जिसमें 35 घरों में कुएं पाए गए। इन सभी कुओं में ब्लीचिंग पाउडर डालकर जल शुद्धिकरण का कार्य कराया गया। साथ ही नागरिकों को जलजनित बीमारियों से बचाव के लिए आवश्यक समझाइश भी दी गई। जन स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों को सलाह दी है कि कुएं के पानी का उपयोग केवल निस्तारी कार्यों में करें

तथा पीने के लिए नल के पानी को छानकर और उबालकर ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा सड़े-गले फल एवं दूषित खाद्य पदार्थों के सेवन से बचने की हिदायत दी गई है। गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए लोगों को लू से बचाव के उपाय अपनाने की भी सलाह दी गई है। जैसे तेज धूप में बाहर निकलते समय गमछा या टोपी पहनें तथा अधिक मात्रा में तरल एवं ताजे पेय पदार्थों का सेवन करें। इस अभियान के माध्यम से विभाग द्वारा नागरिकों को स्वच्छ जल के उपयोग एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है।

कमिश्नर ने खुद किया स्व-गणना, नागरिकों को दिया डिजिटल भागीदारी का संदेश

मोबाइल से भरा गणना पत्रक, जनगणना 2027 को गति देने की पहल

दुर्ग। नगर पालिक निगम।भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत स्व-गणना की प्रक्रिया 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक संचालित की जा रही है। इसी क्रम में नगर निगम दुर्ग के कमिश्नर सुमित अग्रवाल ने अपने चेंबर में मोबाइल के माध्यम से अपने परिवार की स्व-गणना कर नागरिकों को इस अभियान में भागीदारी के लिए प्रेरित किया। कमिश्नर ने बताया कि स्व-गणना की यह डिजिटल व्यवस्था नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से नागरिक 16 से 30 अप्रैल तक स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया सरल, तेज और पारदर्शी

बनती है। उन्होंने जानकारी दी कि पोर्टल पर पूछे गए सभी प्रश्न सरल और सहज भाषा में हैं, जिन्हें मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप के जरिए आसानी से भरा जा सकता है। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद नागरिकों को स्व-गणना आईडी प्राप्त होगी, जो आगे के सत्यापन में सहायक होगी। कमिश्नर सुमित अग्रवाल ने बताया कि स्व-गणना चरण पूर्ण होने के बाद 1 मई से 31 मई तक प्रगणक घर-घर जाकर जानकारी का सत्यापन करेंगे और जनगणना कार्य को अंतिम रूप दिया जाएगा। नगर निगम दुर्ग द्वारा सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में सक्रिय भागीदारी निभाएं और स्व-गणना प्रक्रिया को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक संजय तिवारी द्वारा असमा पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्रास मेमोरियल सेंटर के बाजू, जयस्तंभ चौक, रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित करवाकर व गदा चौक, फरीद नगर रोड स्वर्गीय तुलाराम मेमोरियल स्कूल के पास सुपेला भिलाई, जिला- दुर्ग (छ.ग.) पिन कोड-490023 से प्रकाशित। संपादक : संजय तिवारी, मो. 9200000214 (समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार), समस्त विवादों का निपटारा न्यायलीन क्षेत्र दुर्ग होगा। डाक पंजीयन क्रमांक- सीजी/दुर्ग/लोकतंत्र प्रहरी/2026-28, Email : loktantraprahrinews@gmail.com